# घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 302- शुक्रवार 04- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028


## भारतीय वस्त्र और फैशन उद्योग को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए भारत-फ्रांस के बीच हुआ समझौता

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** भारतीय वस्त्र और फैशन उद्योग को वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से भारत-फ्रांस के बीच पेरिस में प्रीमियर विजन प्रदर्शनी के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के अनुसार भारत टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन (बीटीटीएफ) और रचनात्मक फैशन तथा वस्त्रों के लिए दुनिया के अग्रणी प्लेटफॉर्म 'प्रीमियर विजन एसए' ने बुधवार को (2 सितंबर) एक बहुवर्षीय रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीटीटीएफ कोर कमेटी सदस्य एवं परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष डॉ. ए. शक्तिवेल और प्रीमियर विजन एसए (फैशन डिवीजन) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) फ्लोरेंस रूसन ने हस्ताक्षर किए। इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारतीय वस्त्रों को वैश्विक लक्जरी और उच्च-स्तरीय फैशन उद्योग से जोड़ना,टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत को वॉल्यूम-आधारित (मात्रा-आधारित) निर्यात से आगे बढ़ाकर उच्च-मूल्य तथा डिजाइन-आधारित निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह समझौता जनवरी 2026 में संपन्न हुए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तुरंत बाद आया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजारों का रास्ता और आसान हो गया है। वर्ष 2025 में यूरोपीय संघ का कुल कपड़ा एवं परिधान आयात लगभग 292.8 अरब डॉलर था,जिसमें भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 10.4 अरब डॉलर है। एफटीए के तहत भारत के 99.5 प्रतिशत निर्यात को कवर करने वाली 96.8 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर रियायती पहुंच मिली है, जिसमें कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र पर शून्य-शुल्क लागू होने से भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता में भारी उछाल आएगा। इसमें ज्ञान सत्र एवं प्रतिनिधिमंडल दोनों देश परस्पर व्यापार प्रदर्शनियों में प्रतिनिधिमंडलों,वक्ताओं और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे। बाजार पहुंच व निर्यातखरीदार-विक्रेता बैठकों (बी2बी) और बाजार सूचनाओं के आदान-प्रदान से निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

## भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौता अगले महीने से होगा लागू....

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले महीने से लागू हो जाएगा। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिकारी सूत्रों ने गुरुवार को दी जानकारी में बताया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए अगले महीने से लागू होगा। यह समझौता अगले महीने दोनों देशों की आपसी सहमति से तय तारीख को लागू होगा। अधिकारी ने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों देशों ने 27 अप्रैल को वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एफटीए के तहत न्यूजीलैंड में भारत के 100 फीसदी निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत और न्यूजीलैंड ने सामान और सेवाओं के आपसी व्यापार को बढ़ाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 27 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड में सिरेमिक, कालीन, वाहन एवं उसके कलपुर्जों समेत भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों पर अधिकतम 10 फीसदी तक शुल्क लगता था। न्यूजीलैंड ने 15 साल में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

### तेलंगाना : सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा एक्शन

## वन मंत्री कोंडा सुरेखा की कैबिनेट से छुट्टी,बेटी का बयान बना वजह

**हैदराबाद,03 सितम्बर 2026।** तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने वन मंत्री कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। यह कार्रवाई सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता की कथित टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद के बीच की गई है। इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों ने कोंडा सुरेखा से माफी मांगने की मांग की थी। इसके बाद सुरेखा ने अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब राज्य कांग्रेस की अनुशासन समिति ने कुछ दिन पहले ही कोंडा सुरेखा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की थी। बता दें कि कोंडा सुरेखा के खिलाफ यह कार्रवाई दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक के बाद की गई है। मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को कोंडा सुरेखा को दिल्ली तलब किया था। इस बैठक में शामिल होने के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे थे। टीपीसीसी की अनुशासन समिति ने 25 अगस्त को अपनी रिपोर्ट राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी थी। माना जा रहा है कि समिति ने सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की गई थी।

### दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा का निधन,मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों ने जताया दुःख

**नई दिल्ली,03 सितंबर 2026।** दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा का गुरुवार की सुबह सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया है। उन्होंने 23 मार्च 2022 को दिल्ली के लोकायुक्त की शपथ थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली के मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कहा कि दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति दें। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनका जाना न्याय एवं जनसेवा के क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल दें।

### भारत-बेल्जियम संबंध...पीएम मोदी से मिले प्रधानमंत्री वेवर,जोरावर टैंक,क्लीन एनर्जी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई..

# स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन भारत-बेल्जियम की साझा प्राथमिकताएं : प्रधानमंत्री मोदी

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** भारत,यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। इससे पहले, प्रधानमंत्री डी वेवर ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की और फूल चढ़ाए। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट पर विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक फैल गए हैं। उन्होंने जोरावर टैंक और आंध्र प्रदेश में एक बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट पर सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही। पीएम मोदी ने कहा, 'आज हमारे सहयोग का दायरा पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक फैल गया है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर मिलकर काम कर रहे हैं। हम आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स में से एक को भी विकसित कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं। अगले पांच वर्षों में हम द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य और प्रशिक्षण सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। हम अपनी एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। दोनों देशों के रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व पर भी जोर दिया और कहा, 'भारत और बेल्जियम के संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान हमारी साझा यादों का एक अहम हिस्सा है।

आज,लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच मजबूत संबंध हमें स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं।' 'आज हमने अपने स्टार्टअप्स के बीच संबंध मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ाने पर सहमति जताई।

### दोनों देशों ने निवेश के लिए एक फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म

भारत और ईयू के बीच हुए एफटीए की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने निवेश के लिए एक 'फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म' बनाया है। उन्होंने कहा,'इस साल की शुरुआत में,हमने भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया। यह दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता,विकास और साझा समृद्धि को और मजबूत करेगा। भारत की लगातार आर्थिक प्रगति और इस समझौते ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। आज,हमने इन संभावनाओं को ठोस नतीजों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

### भारत और बेल्जियम व्यापार पर बोले पीएम

हमने 'भारत-बेल्जियम बिजनेस फोरम' को एक नियमित व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। हम दोनों देशों के वित्तीय,फिनटेक और नियामक संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन उपायों के जरिए अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करेंगे।'

## भारत-बेल्जियम के बीच 10 रक्षा रणनीतिक समझौते,भारत में होगा रॉकेट और बारूदी सुरंग रोधी प्रणालियों का उत्पादन

भारत और बेल्जियम ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए 10 बड़े रणनीतिक समझौतें किये हैं। इनके तहत भारत में गोला-बारूद, 70 एमएम रॉकेट,नौसेना की बारूदी सुरंग रोधी प्रणालियां, काउंटर-ड्रोन प्रणाली और समुद्री डीजल इंजन समेत आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण और सह-उत्पादन किया जाएगा। यह सहयोग भारत की 'मेक इन इंडिया'और रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने के साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी का आधार तैयार करेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की 2 से 4 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकन के बीच यहां हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच दीर्घकालिक संरचनात्मक सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही बेल्जियम सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच भी सहयोग समझौता हुआ। प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ बेल्जियम की 15 प्रमुख रक्षा कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इन कंपनियों ने भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर आधुनिक सैन्य साजो-सामान, रॉकेट,नौसैनिक प्रणालियों और ड्रोन रोधी तकनीकों के भारत में निर्माण को लेकर समझौते किए हैं। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के बीच बढ़ती अंतर्संबंधता, समुद्री सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों के आदान-प्रदान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

# सत्येंद्र जैन को कोर्ट से मिली जमानत,दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी ने किया था गिरफ्तार

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन को डीजेबी एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में जमानत दे दी है। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने इसी मामले में गिरफ्तार किए था। सत्येंद्र जैन को दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलके पर जमानत मिली है।

### जैन को एसीबी की टीम ने किया था गिरफ्तार

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के टेंडर में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने बीती 18 अगस्त को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन डीजेबी सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय,बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के प्रोपराइटर पंकज वर्मा शामिल थे।

**एसीबी प्रमुख ने बताई थी कैसे हुई थी हेराफेरी :** एसीबी के प्रमुख सयुंक्त पुलिस आयुक्त विक्रमजीत सिंह ने बताया था कि मामला एसटीपी के उन्नयन और क्षमता बढ़ाने के लिए जारी टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता, टेंडर शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश से जुड़ा था। जांच में सामने आया था कि टेंडर में ऐसी तकनीकी शर्तें शामिल की गईं, जिनसे एक खास तकनीक और उसके प्रदाता यूरोटेक को तौर पर फायदा हुआ। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ा। एसीबी ने इस मामले में 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के साथ धोखाधड़ी,आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। एजेंसी का दावा है कि मामले में पैसों के पूरे लेन-देन और अपराध से अर्जित रकम की जांच जारी है।

**ई-मेल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से खुला खेल :** जांच एजेंसी का दावा था कि निजी पक्षों और सरकारी अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क था। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण में प्रतिबंधात्मक टेंडर शर्तों, कॉरिजेंडम और अन्य दस्तावेजों के आदान-प्रदान की बात सामने आई थी। एसीबी के अनुसार,बाद में इन्हीं में से कुछ शर्तों को डीजेबी के एसटीपी टेंडर में शामिल किया गया। एसीबी ने दावा किया कि तत्कालीन डीजेबी सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में एएन एंटरप्राइजेज के जरिये करीब 1.52 करोड़ रुपये पहुंचे।

### जयशंकर बोले...भारत यूक्रेन जंग खत्म कराने में मदद को तैयार...कहा...जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता करेंगे; ब्लैक सी में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया

**कीव,03 सितम्बर 2026।** केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद के लिए तैयार है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता करने की भी पेशकश की है। जयशंकर ने यह बात गुरुवार को कीव दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। वे यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ मौजूद थे। जयशंकर ने ब्लैक सी में भारतीयों समेत सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाना चाहिए। ब्लैक सी दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। रूस और यूक्रेन से गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने जयशंकर के कीव दौरे को अहम बताया। उन्होंने कहा कि रूसी हमलों के बीच भारतीय विदेश मंत्री की यह यात्रा खास मायने रखती है। सिबिहा ने कहा कि रूस लगातार यूक्रेनी शहरों,बंदरगाहों और नागरिक जहाजों को निशाना बना रहा है। दोनों नेताओं ने ब्लैक सी में जहाजों की आवाजाही सामान्य करने और इससे जुड़ी वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस रुख का भी स्वागत किया,जिसमें भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए युद्ध खत्म करने की बात कहता रहा है।

## देश में छह करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य : शिवराज सिंह चौहान

**मुंबई,03 सितम्बर 2026।** केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुंबई में कहा कि भारत सरकार का देश में छह करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इनमें से साढ़े तीन करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौना ने आज मुंबई में 'लखपति दीदियों' के साथ वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और बैंकरों के साथ अपनी बैठक से पहले स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बातचीत भी की। इसके बाद उन्होंने कहा, आज मैंने मुंबई में लखपति दीदियों के साथ वृक्षारोपण किया। हमारे प्रधानमंत्री ने छह करोड़ लखपति दीदियां बनाने का संकल्प लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 3.5 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं और हम अब छह करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि अनेक औपचारिकताओं और ऋण वितरण में देरी के कारण महिलाओं को अक्सर बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, बैंक अधिकारियों से मिलने से पहले, आज मुंबई में एक बैठक निर्धारित है। हमने पहले स्वयं महिलाओं से परामर्श करने का निर्णय लिया है। वे महिलाएं जो स्वयं सहायता समूहों में काम कर रही हैं और लखपति दीदी बनने के लिए विभिन्न व्यवसाय शुरू कर रही हैं।

## सुप्रीम कोर्ट : सीजेपी के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के बीच बड़ा फैसला,एंट्री-फोटो पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों,पत्रकारों,यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूजर्स और सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया।

**सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई थी?** याचिकाकर्ता ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधित आदेशों को उस सीमा तक रद्द करने की मांग की थी, जहां वे सार्वजनिक हित में दस्तावेजीकरण पर व्यापक रोक लगाते हैं। साथ ही मांग की गई थी कि सार्वजनिक हित से जुड़े दस्तावेजीकरण को नियंत्रित करने वाला कोई भी नियम तर्कसंगतता, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिकारियों की ओर से जारी उन आदेशों को चुनौती दी थी,जिनमें सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है। इसके अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी,इंटरव्यू,ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइवस्ट्रीमिंग के लिए भी लिखित अनुमति की शर्त रखी गई है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है।

**राजस्थान के आदेश में क्या कहा गया था?** याचिका में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 16 अगस्त 2026 को जारी सर्कुलर का हवाला दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य से पहले अनुमति लेना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही स्कूल परिसर में फोटो लेने,वीडियो बनाने, इंटरव्यू करने, ऑडियो रिकॉर्ड करने और लाइवस्ट्रीमिंग के लिए भी पूर्व लिखित अनुमति की व्यवस्था की गई है।

याचिका में अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 19 अगस्त को जारी आदेश का भी उल्लेख है। इसमें बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिषद के स्कूलों में प्रवेश करने या फोटो-वीडियो बनाने से रोकने का निर्देश दिया गया था। याचिका के अनुसार,आजमगढ़,बलिया,बस्ती,बलरामपुर, शामली और आगरा समेत कई अन्य जिलों में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे।

## एनएच-327 के फोरलेन विस्तार को मिली 2,077 करोड़ की मंजूरी...नेपाल,भूटान व बांग्लादेश से संपर्क होगा बेहतर

**सिलीगुड़ी,03 सितंबर 2026।** उत्तर बंगाल के सड़क और परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। दार्जिलिंग जिले में नेशनल हाइवे (एनएच)-327 के बागडोगरा-पानीटंकी-खोरीबाड़ी-गलगलिया सेक्शन के 31.02 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन में बदलने के लिए 2077.18 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह जानकारी गुरुवार को दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिष्ट के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। इससे पूर्वोत्तर भारत के साथ ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को जाने वाले मार्गों तक पहुंच बेहतर होगी। भौगोलिकसंदर्भ राजू बिष्ट ने परियोजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उत्तर बंगाल में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। प्रस्तावित परियोजना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए अहम माना जा रहा है। फोरलेन सड़क बनने से बागडोगरा, नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी और पानीटंकी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत तीन बड़े पुल, एक रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), पांच हाथी अंडरपास और हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा।

हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास बनाए जाने से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। राजू बिष्ट के अनुसार, परियोजना पूरी होने के बाद लोगों और माल की आवाजाही तेज होगी तथा क्षेत्र की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार आएगा। इससे बागडोगरा एयरपोर्ट तक पहुंच आसान होने के साथ क्षेत्र के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी। यात्रा समय और परिवहन लागत कम होने से किसान,चाय उत्पादक, बागवानी से जुड़े लोग,व्यापारी,छात्र,पर्यटक और स्थानीय कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह परियोजना उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली संपर्क को और मजबूत करेगी। साथ ही नेपाल,भूटान और बांग्लादेश की ओर जाने वाले मार्गों तक पहुंच भी बेहतर होगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक महत्ता को देखते हुए इस परियोजना को केवल क्षेत्रीय सड़क विकास तक सीमित नहीं माना जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क से उत्तर बंगाल की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बीच आवश्यक वस्तुओं,सेवाओं और लोगों की आवाजाही अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

## संपादकीय

# चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट

जिस देश ने दुनिया को चीनी बनाना सिखाया,वहां आज आम आदमी पूछ रहा है–मिठास इतनी महंगी क्यों हो गई?

भारत में चीनी सिर्फ रसोई की एक सामान्य वस्तु नहीं है। चाय के प्याले से लेकर मिठाई की दुकान तक,त्योहारों से लेकर रोजमर्रा के खान-पान तक, चीनी भारतीय जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब इसी चीनी की कीमत आम परिवार के मासिक बजट को प्रभावित करने लगे तो सवाल केवल बाजार का नहीं रहता,बल्कि अर्थव्यवस्था, कृषि नीति और सरकारी प्रबंधन का भी बन जाता है। देश के कई हिस्सों में चीनी की खुदरा कीमतों में तेजी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल भारत में घरेलू बाजार इतना दबाव में क्यों है? जिस देश के पास विशाल गन्ना उत्पादन,सैकड़ों चीनी मिलें और करोड़ों किसानों से जुड़ा पूरा चीनी उद्योग है, वहां उपभोक्ता को महंगी चीनी क्यों खरीदनी पड़ रही है?

सरकार और विपक्ष के पास इसके अलग-अलग जवाब हैं। विपक्ष इसे सरकारी नीतियों की विफलता बता रहा है,जबकि सरकार उत्पादन में कमी, मौसम की मार,त्योहारी मांग,वैश्विक परिस्थितियों और जमाखोरी जैसे अनेक कारण गिना रही है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। चीनी की कीमत किसी एक फैसले से तय नहीं होती। खेत में गन्ने की पैदावार से लेकर चीनी मिल की उत्पादन क्षमता,गन्ने का मूल्य,एथेनॉल उत्पादन,निर्यात नीति,घरेलू स्टॉक,वैश्विक कीमतें,परिवहन लागत और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग–इन सभी का असर बाजार पर पड़ता है।

यही वजह है कि चीनी की महंगाई को केवल 'एथेनॉल के कारण' या केवल 'जमाखोरी के कारण' बताना वास्तविक समस्या को बहुत सरल बना देना होगा। मौसम भी इस कहानी का बड़ा किरदार है। गन्ना ऐसी फसल है जिस पर मौसम का असर तत्काल नहीं,बल्कि कुछ समय बाद दिखाई देता है। अत्यधिक बारिश,सूखा या बीमारी उत्पादन की पूरी गणित बदल सकती है। आज खेत में हुई क्षति कल मिलों के उत्पादन में दिखाई देती है और कुछ महीनों बाद वही असर बाजार की कीमतों में पहुंचता है।

**लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इन बदलावों का अनुमान लगाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?**

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सरकार केवल आंकड़ों की घोषणा करने वाली संस्था नहीं हो सकती। उसे आने वाली कमी का अनुमान पहले लगाना होगा, स्टॉक की स्थिति पर लगातार नजर रखनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर आयात या अन्य नीतिगत कदम समय रहते उठाने होंगे। यदि आयात की जरूरत पड़ती है तो उसे संकट पैदा होने के बाद की प्रतिक्रिया के बजाय संकट की आशंका के समय की तैयारी बनाया जाना चाहिए। यहां एथेनॉल नीति भी महत्वपूर्ण है। भारत को पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की जरूरत है। इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार तैयार करने में मदद मिल सकती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन भी उतना ही जरूरी है। गन्ने से चीनी बनेगी या एथेनॉल–यह सवाल अब केवल उद्योग का सवाल नहीं है। यह राष्ट्रीय नीति का सवाल है। किसान चाहता है कि उसे गन्ने का बेहतर मूल्य मिले। चीनी मिल चाहती है कि उसकी लागत निकले और उद्योग आर्थिक रूप से टिकाऊ रहे। सरकार चाहती है कि ऊर्जा नीति आगे बढ़े। और उपभोक्ता चाहता है कि उसे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु उचित कीमत पर मिले।

**इन चारों हितों के बीच संतुलन ही असली चुनौती है।**

**दूसरी बड़ी चुनौती है जमाखोरी।**

यदि देश में पर्याप्त चीनी उपलब्ध है और इसके बावजूद कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतें बढ़ाई जा रही हैं,तो सरकार को कठोर कार्रवाई करनी होगी। स्टॉक सीमा लगाना और निरीक्षण करना जरूरी कदम हैं,लेकिन इनका असर तभी माना जाएगा जब बाजार में वास्तविक कीमतों पर उसका परिणाम दिखाई दे। सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि उसके आदेश फाइलों में कितने प्रभावी हैं और बाजार में कितने।

विपक्ष का सत्याग्रह भी इसी बिंदु पर महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक दलों को जनता की रसोई का सवाल उठाना चाहिए। लेकिन महंगाई के मुद्दे को केवल राजनीतिक नारे में बदल देना भी पर्याप्त नहीं है। विपक्ष को आंकड़ों के साथ यह बताना होगा कि कौन-सी नीति गलत है, उसका विकल्प क्या है और वह विकल्प किसान तथा उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा कैसे करेगा। सत्ता पक्ष को भी विपक्ष के आरोपों को केवल राजनीतिक विरोध मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है और सरकार का काम उन सवालों का जवाब देना।

**लेकिन जवाब केवल आंकड़ों से नहीं,परिणामों से होना चाहिए।**

यदि सरकार कहती है कि स्टॉक पर्याप्त है तो उपभोक्ता को राहत क्यों नहीं मिल रही? यदि जमाखोरी जिम्मेदार है तो दोषियों पर कार्रवाई कितनी हुई? यदि उत्पादन कम है तो अगले सीजन की तैयारी क्या है? यदि आयात आवश्यक था तो निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया? और यदि बाजार शीघ्र सामान्य होने वाला है तो सामान्य कीमत का इंतजार कब खत्म होगा?

ये सवाल किसी राजनीतिक दल के नहीं,आम उपभोक्ता के सवाल हैं।

चीनी की महंगाई का असर भी केवल एक किलो चीनी तक सीमित नहीं रहता। मिठाई,बेकरी उत्पाद, पेय पदार्थ और कई खाद्य वस्तुओं की लागत इससे प्रभावित होती है। त्योहारों के मौसम में इसका असर और व्यापक हो सकता है। यानी चीनी महंगी होती है तो उसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कई दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

इसलिए सरकार को चीनी को केवल एक कृषि उत्पाद या एक औद्योगिक वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की खपत से जुड़ी आवश्यक वस्तु है।

भारत ने सदियों पहले गन्ने के रस से मिठास निकालने की तकनीक विकसित की थी। चीनी का यह सफर भारत से दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा। आज वही भारत दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादकों में शामिल है। ऐसे में यह विडंबना ही है कि उत्पादन की इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद उपभोक्ता को कीमतों के उतार-चढ़ाव से जूझना पड़ रहा है।

समस्या का स्थायी समाधान हर संकट में निर्यात रोकना,फिर निर्यात खोलना, जरूरत पड़ने पर आयात करना या अचानक स्टॉक सीमा लगा देना नहीं हो सकता। जरूरत है एक ऐसी दीर्घकालिक चीनी नीति की जिसमें उत्पादन, किसान, उद्योग, एथेनॉल और उपभोक्ता–सभी को साथ लेकर चला जाए। देश को यह तय करना होगा कि चीनी उद्योग में कितना उत्पादन घरेलू खपत के लिए सुरक्षित रखा जाए,कितना एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो, कितना निर्यात किया जा सकता है और कितना बफर स्टॉक आवश्यक है। मौसम और उत्पादन के शुरुआती संकेतों के आधार पर नीति में समय रहते बदलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

क्योंकि महंगाई आने के बाद उसका इलाज करना आसान नहीं होता। बेहतर है कि सरकार उस समय तैयारी करे जब संकट अभी दिखाई नहीं दे रहा हो। आज चीनी की कीमत पर राजनीतिक बहस हो रही है। कल किसी दूसरी खाद्य वस्तु की बारी हो सकती है। इसलिए यह मामला किसी एक दल की जीत या हार का नहीं, देश की खाद्य मूल्य-व्यवस्था की मजबूती का सवाल है।

आम आदमी को यह जानने में दिलचस्पी नहीं कि महंगाई की जिम्मेदारी किस मंत्रालय,किस नीति या किस सरकार पर है। उसकी प्राथमिकता सीधी है–रसोई का खर्च नियंत्रण में रहे।

सरकार को यह समझना होगा कि महंगाई के आंकड़ों में आधा प्रतिशत की गिरावट भी उस परिवार के लिए पर्याप्त राहत नहीं है जिसके घरेलू खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चीनी की मिठास तभी सार्थक है, जब किसान की मेहनत का सम्मान हो,उद्योग की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे और उपभोक्ता की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

भारत को चीनी चाहिए–लेकिन ऐसी चीनी नहीं जिसकी मिठास बाजार में हो और कड़वाहट आम आदमी की जेब में...देश ने दुनिया को मिठास बनाना सिखाया था। अब समय है कि भारत अपनी चीनी नीति में भी ऐसी व्यवस्था बनाए,जिसमें किसान को न्याय, उद्योग को स्थिरता और उपभोक्ता को राहत मिले। यही आर्थिक सुशासन की असली कसौटी है।

# युगों से जीवंत है कृष्ण का विराट व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन

## अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक हैं कृष्ण

भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी का पावन पर्व सम्पूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनमानस के नायक,योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति,अध्यात्म और जीवन-दर्शन में श्रीकृष्ण के विराट व्यक्तित्व और उनके लोककल्याणकारी संदेशों का स्मरण कराने वाला पर्व है।



योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,
नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार,भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के संयोग में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण हुआ था। अत्याचारी कंस के आतंक से त्रस्त मथुरा में श्रीकृष्ण का जन्म अन्याय और अधर्म के विरुद्ध धर्म,सत्य और न्याय की विजय की आशा का प्रतीक बना। पौराणिक मान्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के पूर्णावतार माने जाते हैं और उनके व्यक्तित्व में बाल-सुलभ चंचलता,अद्भुत करुणा,अनुपम प्रेम, असाधारण पराक्रम,दूरदर्शी कूटनीति तथा गहन आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने भगवद्गीता के माध्यम से कर्म,धर्म और कर्तव्य का ऐसा कालजयी संदेश दिया, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। इस वर्ष 4 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण की 5253वीं जन्माष्टमी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों,भजन-कीर्तन और मध्यरात्रि में भगवान के जन्मोत्सव के साथ यह पर्व भारतीय सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

जन्माष्टमी के दिन देशभर में मंदिरों को सजाया जाता है,लोग रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे शंख और घंटों की ध्वनि के जरिये भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बाल्याकाल में अनेकों लीलाएं की,जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसी ही अनेक लीलाओं का मंचन किया जाता है। सही मायनों में श्रीकृष्ण हमारे इतिहास के अभिन्न अंग हैं,जिनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व जितना मोहक था,उतना ही रहस्यमयी भी और उतनी ही अनोखी थी उनकी लीलाएं। बाल्यावस्था से लेकर जीवनपर्यन्त लीलाएं करते रहे श्रीकृष्ण में कभी भगवान के दर्शन होते हैं तो कभी वे एक साधारण मानव सरीखे प्रतीत होते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि मानव के रूप में भी श्रीकृष्ण उतना ही आकर्षित करते हैं,जितना कि भगवान के रूप में। उनका एक-एक कार्य मन में गहरा स्थान बना जाता है। उनके आदर्श, उनके जीवन की विद्वत्ता, वीरता,कूटनीति, योगी सदृश उज्जवल,निर्मल एवं प्रेरणादायक पक्ष,सब हमारे लिए अनुकरणीय हैं। श्रीकृष्ण को प्रेम एवं मित्रता के अनुपम प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। बचपन के निर्धन मित्र सुदामा को उन्होंने अपने राज्य में जो मान-सम्मान दिया,वह मित्रता का अनुकरणीय उदाकरण बना। श्रीकृष्ण की लीलाओं को समझना जहां पहुंचे हुए ऋषि-मुनियों और बड़े-बड़े विद्वानों के बूते से भी बाहर था, वहीं अनपे , गंवार माने जाते रहे निरक्षर और



भोले-भाले ग्वाले और गोपियां उनका सानिध्य पाते हुए उनकी दिव्यता का सुख पाते रहे। उन्हें कन्हैया कहें या कृष्ण, पीताम्बर कहें या वासुदेव या फिर देवकीनंदन अथवा यशोदानंदन,वास्तव में श्रीकृष्ण का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे महाभारत काल के ऐसे आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दृष्टा रहे,जिन्होंने धर्म,सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दुर्जनों का संहार किया। वे शांति,प्रेम एवं करूणा के साकार रूप थे। महाभारत युद्ध के समय शांति के सभी प्रयास असफल होने पर उन्होंने संशयग्रस्त धनुर्धारी अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देकर कर्त्तव्य मार्ग पर अग्रसर किया और अन्याय की सत्ता को उखो ने के लिए अपने ही कौरव भाईयों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें अपने कर्मों का पालन करने के लिए गीता का उपदेश दिया। युद्ध के समय वे हर पल धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म करने वालों के खिलाफ खड़े नजर आए,इसीलिए उन्हें अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। गीता में उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा था:-

**यदा यदा हि धर्मस्य**
**ग्लानिर्भवति भारत।**
**अभ्युत्थानम धर्मस्य**
**तदात्मानं सृजाम्यहम।।**

अर्थात् हे भारत! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है,तब-तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं अर्थात् साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। बाल्याकाल से लेकर बडें होने तक श्रीकृष्ण की अनेक लीलाएं विख्यात हैं। श्रीकृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम का घमंड तो ने के लिए हनुमान जी का आव्हान किया था,जिसके बाद हनुमान ने बलराम की वाटिका में जाकर बलराम से युद्ध किया और उनका घमंड चूर-चूर कर दिया था। श्रीकृष्ण ने नररकासुर नामक असुर के बंदीगृह से 16100 बंदी महिलाओं को मुक्त कराया था, जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाने पर उन महिलाओं ने श्रीकृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाई और तब श्रीकृष्ण ने उन सभी महिलाओं को अपनी रानी होने का दर्जा देकर उन्हें सम्मान दिया था। अपने एक उपदेश में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा था:-

**परित्राणाय साधूनां**
**विनाशाय च दुष्कृताम।**
**धर्मसंस्थापनार्थाय**
**सम्भवामि युगे युगे।।**

अर्थात् साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूं।

श्रीकृष्ण का स्वरूप कितना दिव्य था, इसकी अनुभूति इसी से हो जाती है कि एक ओर जहां अपने स्तनों पर विष लेप कर मां का रूप धारण कर दूध पिलाने आई राक्षसी पूतना का दूध पीकर श्रीकृष्ण उसे मां का सम्मान देते हैं तो दूसरी ओर उसकी दुष्टता के लिए उसका वध भी करते हैं। श्रीकृष्ण ने लंबे समय तक द्वारका पर शासन किया,इसीलिए उन्हें द्वारकाधीश नाम से भी जाना जाता है। 36 वर्षों तक द्वारका पर शासन करने के बाद वे परम धाम को प्राप्त हुए थे। पाप-पुण्य,नैतिक-अनैतिक,सत्य-असत्य से परे पूर्ण पुरूष की अवधारणा को साकार करते श्रीकृष्ण भारतीय परम्परा के ऐसे प्रतीक हैं,जो जीवन का प्रतिबिम्ब हैं और सम्पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनका चित्र जनमानस के हृदय पटल पर एक कुशल नेतृत्वकर्ता,योद्धा,गृहस्थी, सारथी,योगीराज,देवता इत्यादि विविध रूपों में अंकित है। श्रीकृष्ण बंधन भी हैं और मुक्ति भी,एक ओर जहां वे अपने भक्तों को अपने आकर्षण में बांधते हैं तो उन्हीं भक्तों को मोह-माया के बंधन से मुक्त भी करते हैं।

# विकसित भारत : मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे हम?

किसी देश के भविष्य के बारे में बात करते हुए उसके सामने कोई बड़ा लक्ष्य रख देना आसान है लेकिन यह समझ पाना मुश्किल होता है कि ऐसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश ने अब तक कितनी तैयारी की है और जिस रास्ते पर वह चल रहा है, वह वास्तव में उसे वहां ले भी जाएगा या नहीं? भारत के सामने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है। यानी आजादी के सौ साल पूरे होने तक भारत को उस स्थिति में पहुंचाना है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी और मजबूत हो, नागरिकों का जीवन बेहतर हो और देश दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी निर्णायक जगह बना चुका हो।



प्रो.महेश गुप्ता
नई दिल्ली

अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि विकसित भारत का लक्ष्य सुनने में जितना आकर्षक है,उसकी गंभीरता उतनी ही अधिक है। आखिर विकसित राष्ट्र होना केवल इतना नहीं है कि जीडीपी का आकार बढ़ जाए या देश दुनिया की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आ जाए। बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई आर्थिक विस्तार होता है तो उसका असर देश के सामान्य नागरिक के जीवन पर कितना पड़ेगा? इसी सवाल के उत्तर में विकसित भारत की चर्चा को केवल राजनीतिक नारे या सरकारी उपलब्धियों की सूची से अलग करके देखने की जरूरत महसूस होती है। पिछले दस-बारह सालों में देश में कई सार्थक बदलाव हुए हैं। डिजिटल तकनीक का विस्तार इसका सबसे दिखाई देने वाला उदाहरण है। जिस देश में कभी बैंक खाता,पहचान और सरकारी सुविधा तक पहुंच अपने आप में बड़ी समस्या हुआ करती थी,वहां डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे ने करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन को किस प्रकार बदल दिया है,यह हमारे सामने है। सड़कों, रेल,बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण की गति भी तीव्र हुई है। रक्षा उत्पादन में घरेलू क्षमता बढ़ाने की कोशिश हुई है। ऊर्जा के क्षेत्र में नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव उस सोच का है जिसमें भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में देखने के बजाय उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश दिखाई देती है। यह बदलाव साधारण नहीं है। आजादी के बाद लंबे समय तक भारत की आर्थिक बहस में कृषि का संकट और फिर सर्विस सेक्टर की सफलता प्रमुख विषय रहे। मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर अपेक्षित मजबूती से नहीं उभर पाया। चीन की आर्थिक सफलता महत्वपूर्ण है, इसमें हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार और औद्योगिक क्षमता पैदा किए बिना किसी विशाल आबादी वाले देश को ऊंची आय वाले समाज में बदलना कठिन है। इसलिए सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स,रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और दूसरी बुनियादी औद्योगिक क्षमताओं में निवेश को केवल कुछ नई फैक्ट्रियों तक सीमित मानना उचित नहीं होगा। इसके पीछे एक बड़े आर्थिक बदलाव की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि देश अपने लिए जरूरी चीजें बनाने की क्षमता विकसित करे,वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाओं में जगह बनाए और ऐसा औद्योगिक ढांचा खड़ा करे जो आने वाले दशकों में लाखों लोगों के लिए अवसर पैदा कर सके। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तो अपरिहार्य है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें ऊर्जा को महत्व देकर देखना चाहिए। जाहिर है,औद्योगिकीकरण होगा तो ऊर्जा चाहिए। शहर बढ़ेंगे तो बिजली चाहिए। रेलों को बिजली से चलाने आदि में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलेगा तो ऊर्जा की दरकार बढ़ेगी। इसलिए परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और दूसरे स्रोतों पर एक साथ विचार करना पड़ेगा। एल्युमिनियम,स्टील जैसी बुनियादी धातुओं और दूसरे औद्योगिक कच्चे माल की क्षमता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। निःसंदेह देश को विकसित बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है। चीन और विकसित एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करें तो यह अंतर साफ दिखाई देता है। प्रति व्यक्ति आय का यह अंतर कई समस्याओं की जड़ है। हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर एकजुट हो कर काम करें, यह सही है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी तो सोचना होगा कि आर्थिक विकास के प्रकाश को उस बिंदु तक कैसे ले जाया जाए जहां उसकी रोशनी समाज के उन अंधकार भरे हिस्सों तक भी पहुंचे जो आज उससे पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? इसमें दो-राय नहीं है कि देश में गरीबी कम हुई है,लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, उपभोग का बाजार फैला है। यह परिवर्तन वास्तविक है लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार और स्वच्छता जैसे क्षेत्र हैं जहां अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर एक परिवार की आय बढ़ जाए लेकिन उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा न मिले, उसके पास मोबाइल और इंटरनेट हो लेकिन गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उसे जमीन बेचनी पड़े तो क्या हम इसे विकसित समाज कहेंगे? इसलिए विकसित भारत का सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था का प्रश्न नहीं है,यह हमारे लिए सामाजिक जीवन का सवाल भी है।हमारे देश में जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो रोजगार का प्रश्न सबसे ज्यादा असहज करने वाला होता है। भारत उन देशों में है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर इस युवा आबादी को लाभ के स्रोत में परिवर्तित करना है तो उसके लिए शिक्षा चाहिए, कौशल चाहिए और ऐसे रोजगार चाहिए जिनसे व्यक्ति अपने जीवन को आगे ले जा सके। अगर उद्योग बढ़ता है लेकिन रोजगार पर्याप्त नहीं बढ़ता तो विकास की तस्वीर अधूरी रह जाती है। जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है तो इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। देश में कितने बड़े कारखाने लगे,यह महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनके आसपास कितने छोटे उद्योग खड़े हुए, कितने लोगों को स्थायी काम मिला, कितने कस्बे आर्थिक गतिविधि के नए केंद्र बने और कितने ग्रामीण परिवारों के जीवन में इसका असर पहुंचा।

# जौहरः राख नहींअस्मिता की आग

जौहर भारतीय इतिहास की उन घटनाओं में से है, जिसकी स्मृति आज भी राजस्थान की माटी,लोककथाओं और वीर-रस की परंपरा में गहराई से जीवित है। जौहर को केवल अग्नि में प्राण देने की घटना मान लेना उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को सीमित कर देना होगा। इसके पीछे युद्ध, सत्ता-संघर्ष,स्त्री की असुरक्षा, पराजय की आशंका और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की जटिलता थी। इसलिए जौहर की चर्चा भावनाओं के साथ-साथ इतिहास-बोध और मानवीय संवेदना के साथ भी होनी चाहिए।



डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

राजपूत इतिहास में वीरता केवल रणभूमि में तलवार उठाने तक सीमित नहीं रही। पुरुषों के शौर्य के साथ स्त्रियों के त्याग,साहस और आत्मसम्मान की कथाएँ भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मावती से जुड़ी जौहर की लोकस्मृति हो या मेवाड़ और राजस्थान की अन्य वीरांगनाओं की गाथाएँ–इन कथाओं ने राजपूती अस्मिता की ऐसी छवि निर्मित की, जिसमें स्वाभिमान को सर्वोच्च मूल्य माना गया।

जौहर की ज्वाला जागी है,सारा सिंधु सुखाने को–जैसी ओजपूर्ण पंक्तियाँ इसी सामूहिक स्मृति की अभिव्यक्ति हैं। इनमें इतिहास के उस दौर की पीड़ा,आक्रोश और आत्मसम्मान की भावना दिखाई देती है। किंतु आज इन भावनाओं को समझते हुए यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान समाज में किसी



समुदाय के विरुद्ध घृणा या वैमनस्य पैदा करने का माध्यम न बनाया जाए।

जौहर का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष स्त्री की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन युद्धों में पराजित राज्यों की महिलाओं के सामने अपहरण, हिंसा, दासता और जबरन नियंत्रण जैसी आशंकाएँ मौजूद थीं। उस दौर की सामाजिक संरचना में स्त्रियों के पास आज जैसी कानूनी सुरक्षा, संस्थागत संरक्षण और स्वतंत्र निर्णय के आधुनिक विकल्प नहीं थे। ऐसे वातावरण में जौहर जैसी घटनाएँ सामने आईं। उन्हें समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को वर्तमान सामाजिक और कानूनी मानकों से अलग करके देखना आवश्यक है। लेकिन इतिहास की त्रासदी को समझना और उसका अंधा महिमामंडन करना दो अलग बातें हैं। आज जौहर हमारे लिए अनुकरण का मार्ग नहीं हो सकता। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में स्त्री की गरिमा की रक्षा मृत्यु के माध्यम से नहीं,बल्कि कानून, शिक्षा, सामाजिक चेतना और न्यायपूर्ण संस्थाओं के माध्यम से होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए जिसमें किसी महिला को अपनी अस्मिता बचाने के लिए जीवन समाप्त करने जैसी स्थिति का सामना ही न करना पड़े। राजपूती वीरांगनाओं की स्मृति का सम्मान इसी दृष्टि से अधिक सार्थक होगा। उनके साहस को केवल मृत्यु से जोड़ना उनके संघर्ष और व्यक्तित्व को सीमित कर देना होगा। उनके भीतर मौजूद आत्मसम्मान, संकट में निर्णय लेने का साहस और विपरीत परिस्थितियों में मानसिक दृढ़ता को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। इतिहास में दर्ज बलिदान हमें यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आज हम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं।

इसी तरह राजपूत वीरों की तलवार और बलिदान की गाथाएँ भी केवल युद्ध-रोमांच की कहानियाँ नहीं हैं। वे अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों,क्षेत्रीय स्वायत्तता और सम्मान की रक्षा के संघर्षों का हिस्सा थीं।

**जिन शेरों ने धरा सींच दी,**
**लहू बहाकर सीने से...**

जैसी पंक्तियाँ उस वीर परंपरा को स्मरण करती हैं, जिसने राजस्थान के इतिहास और लोक-संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया।

इतिहास की स्मृति तभी स्वस्थ होती है,जब उसमें गर्व के साथ विवेक भी हो। हमें अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद करना चाहिए,लेकिन इतिहास को वर्तमान की नफरत में बदलने से बचना चाहिए। किसी ऐतिहासिक संघर्ष में शामिल व्यक्तियों या समूहों के आधार पर आज के पूरे समुदायों को दोषी ठहराना न इतिहाससम्मत है और न सामाजिक रूप से उचित।

विशेष रूप से साहित्य और कविता की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। वीर-रस की कविता समाज में आत्मविश्वास,साहस और देशप्रेम की भावना पैदा कर सकती है। लेकिन वही कविता यदि किसी समुदाय के प्रति घृणा को बढ़ावा देने लगे तो उसका रचनात्मक उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जय भवानी और जय माता पद्मावती जैसे उद्घोषों को सांस्कृतिक स्मृति और श्रद्धा के रूप में देखा जाना चाहिए,न कि किसी के प्रति वैमनस्य के राजनीतिक नारे के रूप में।

# मेरे कान्हा : जन्माष्टमी विशेष

डॉ. प्रियंका सौरभ,हिसार,हरियाणा

जन्माष्टमी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना में गहराई से रचा-बसा ऐसा पर्व है,जो केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, स्मृतियों और जीवन-मूल्यों का उत्सव है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि जब मंदिरों में शंखनाद गूंजता है और 'नंद के घर आनंद भयो'की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय कर देती है, तब मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। घरों,मंदिरों और गलियों में सजी झांकियों के बीच झूले में विराजमान नन्हे कान्हा श्रद्धा,प्रेम और उल्लास का केंद्र बन जाते हैं। जन्माष्टमी पर छोटे-छोटे बच्चों को कृष्ण का रूप देने की परंपरा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। मोरपंख, पीतांबर,मुकुट,बांसुरी और नटखट मुस्कान से सजे बच्चे जब सामने आते हैं,तो वातावरण में सहज ही आनंद भर जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कान्हा बनाना केवल इतना ही है? क्या मुकुट पहनाने और बांसुरी थमाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? वास्तव में,बच्चे को कान्हा बनाना केवल उसकी बाहरी सज्जा नहीं,बल्कि उसके भीतर जीवन-मूल्यों के बीज बोने का अवसर है। यह अवसर हमें बताता है कि कृष्ण केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं,बल्कि प्रेम, मित्रता, करुणा,साहस,विवेक और कर्मशीलता के भी प्रतीक हैं। जब कोई बच्चा कान्हा का रूप धारण करता है,तो उसके साथ कृष्ण के चरित्र और उनके जीवन-संदेश को समझाना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। कृष्ण का बाल-रूप भारतीय जनमानस में सदियों से विशेष प्रिय रहा है। उनकी नटखटता में जीवन का उल्लास है,उनकी बांसुरी में प्रेम और संवाद की मधुरता है,उनकी मित्रता में आत्मीयता है और कंस के विरुद्ध संघर्ष में अन्याय के सामने खड़े होने का साहस। यही कारण है कि कृष्ण की कथाएँ बच्चों को सहज रूप से आकर्षित करती हैं। इन कथाओं में मनोरंजन भी है और जीवन की गहरी सीख भी।



आज के समय में इस सीख की आवश्यकता और बढ़ गई है। आज का बचपन बदल चुका है। आंगन,चौपाल और खुले मैदानों की जगह मोबाइल, कंप्यूटर,वीडियो गेम और सोशल मीडिया ने ले ली है। तकनीक ने बच्चों के लिए ज्ञान और संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं, लेकिन उसके साथ एक चुनौती भी आई है–बच्चों का अपनी सांस्कृतिक जड़ों और वास्तविक सामाजिक संबंधों से दूर होना। ऐसे समय में जन्माष्टमी जैसे पर्व बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। किंतु हमें सावधान रहना होगा कि त्योहार केवल फोटो खिंचवाने, आकर्षक वेशभूषा पहनाने और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने तक सीमित न हो जाए। यदि बच्चा कान्हा की वेशभूषा तो पहन ले, लेकिन प्रेम, सत्य, करुणा और साहस को अपने व्यवहार में न उतारे,तो त्योहार का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

**सूचना**

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

**सम्पादक**

C M Y K

# शक्कर की महंगाई पर कांग्रेस का सत्याग्रह,सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

## विवेकानंद प्रतिमा के सामने प्रदर्शन...कांग्रेस बोली-40 रुपये वाली शक्कर 60-75 रुपये तक पहुंची,सरकार बताए महंगाई का जिम्मेदार कौन?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

रसोई के बजट पर बढ़ते बोझ को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने गुरुवार को विवेकानंद प्रतिमा के सामने सत्याग्रह कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि,कांग्रेस ने कीमतों में 40 से 78 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने का दावा किया है, जबकि उपलब्ध ताजा बाजार रिपोर्टों में विभिन्न शहरों में खुदरा कीमतें लगभग 60 से 75 रुपये प्रति किलो तक बताई गई हैं। 2 सितंबर तक अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत में कुछ गिरावट आकर करीब 62.57 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी।

**कांग्रेस का आरोप...नीतियों का खामियाजा उपभोक्ता भुगत रहा :** कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों के कारण घरेलू बाजार में शक्कर की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बढ़ा है। पार्टी ने इथेनॉल के लिए गन्ने/शक्कर के डायवर्जन, शक्कर के निर्यात और घरेलू स्टॉक को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए। लेकिन इस आरोप पर सरकार का पक्ष अलग है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा मूल्य वृद्धि को केवल इथेनॉल डायवर्जन से जोड़ना सही नहीं है। सरकार के अनुसार इथेनॉल के लिए डायवर्जन का हिस्सा 2022-23 के करीब 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% हुआ है। सरकार ने कीमत बढ़ने के पीछे कम उत्पादन, त्योहारी मांग, मौसम से फसल को नुकसान, वैश्विक आपूर्ति और कुछ व्यापारियों/मिलों द्वारा जमाखोरी-सट्टेबाजी जैसे कारण भी बताए हैं। यानी शक्कर की महंगाई पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन असली परीक्षा बाजार में कीमत कम करने की है।

**'प्यास लगने पर कुआं खोदने' का तंज :** सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने केंद्र सरकार द्वारा कच्ची शक्कर के आयात के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे 'प्यास लगने पर कुआं खोदने' जैसा कदम बताया। उनका कहना था कि आयातित शक्कर को भारत पहुंचने,रिफाइन होने और बाजार तक आने में समय लगेगा,जबकि आम उपभोक्ता आज महंगी शक्कर खरीदने को मजबूर है। दरअसल,केंद्र ने अगस्त में 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची शक्कर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। बाद में आयातकों की शिपिंग संबंधी दिक्कतों को देखते हुए कच्ची शक्कर को रिफाइन कर घरेलू बाजार में बेचने की समयसीमा भी बदली गई।

**सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए भी उठाए कदम :** महंगाई पर विपक्ष के हमले के बीच केंद्र रकार का कहना है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाई गई है और मिलों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं के लिए भी 15 दिनों की खपत से अधिक स्टॉक रखने पर रोक की व्यवस्था लागू की गई। सरकार ने 15 सितंबर से चीनी डीलरों की स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल करने की घोषणा भी की है, जिसका उद्देश्य जमाखोरी और कृत्रिम कमी पर अंकुश लगाना है।

### महंगाई के बीच आंकड़ों का अपना खेल...

कांग्रेस का कहना है कि देश में करीब 28 लाख मीट्रिक टन मासिक खपत के मुकाबले पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के बावजूद सरकार की नीतियों ने संकट बढ़ाया। दूसरी ओर, उद्योग के एक प्रमुख प्रतिनिधि ने अगस्त में कहा था कि देश में वास्तविक शक्कर की कमी नहीं है और हालिया तेजी में सट्टेबाजी व जमाखोरी की भूमिका अधिक हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में उत्पादन करीब 27.9 मिलियन टन रहा और घरेलू खपत लगभग 28-28.5 मिलियन टन रहने का अनुमान था। इससे तस्वीर साफ है कि शक्कर की कीमत बढ़ने की वजह एक ही नहीं है–उत्पादन,शुरुआती स्टॉक,त्योहारी मांग,निर्यात,इथेनॉल डायवर्जन,वैश्विक बाजार और जमाखोरी सभी कारक चर्चा में हैं।

### कांग्रेस की मांग...अधिकतम खुदरा मूल्य तय करे सरकार...

बालकृष्ण पाठक ने सरकार से तत्काल अधिसूचना जारी कर शक्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य 40 रुपये प्रति किलो निर्धारित करने और इससे अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने की मांग की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा सोनी ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बढ़ती कीमतों का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग की रसोई पर पड़ रहा है।

### सवाल यह नहीं कि आरोप किसका, सवाल यह कि राहत कब?

**शक्कर की कीमतों पर कांग्रेस का सत्याग्रह अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सरकार की ओर से स्टॉक सीमा,आयात और निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं,लेकिन उपभोक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल खुदरा बाजार की कीमत है। यदि सरकार का दावा है कि पर्याप्त स्टॉक है और जमाखोरी पर कार्रवाई हो रही है,तो फिर उपभोक्ता को सामान्य कीमत पर शक्कर कब मिलेगी? और यदि विपक्ष का दावा सही है कि नीतिगत फैसलों से संकट पैदा हुआ है,तो उन फैसलों की समीक्षा कब होगी?**

*आखिर शक्कर का खेल आंकड़ों में कितना भी मीठा क्यों न दिखे,रसोई में महंगी शक्कर आम आदमी के लिए कड़वा सच बन चुकी है।*

# असोला स्कूल में संस्कृत सप्ताह समारोह

## गीत-नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने बांधा समां

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असोला में संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। सप्ताहभर विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर संस्कृत भाषा के प्रति अपनी रुचि और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह के प्रथम दिवस मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दीप ज्योति मंत्र और सरस्वती वंदना से विद्यालय परिसर संस्कृतमय हो उठा। विद्यार्थियों ने संस्कृत के सरल शब्दों एवं वाक्यों का बोलचाल में प्रयोग करते हुए अपना परिचय, प्रश्नोत्तरी,अभिनय सहित विभिन्न रोचक प्रस्तुतियां दीं। सप्ताहभर नृत्य, नाटक,संस्कृत गीत,सूक्ति,श्लोक,वाद-विवाद, निबंध लेखन,भाषण,चित्रकला

और अभिनीत कहानी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संस्कृत शिक्षिका श्रीमती दीपलता देशमुख के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। संस्कृत गीतों की प्रस्तुति एवं उन पर आधारित नृत्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ... गौर ने विद्यार्थियों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और संस्कारों को समझने तथा संरक्षित रखने में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत को केवल विषय के रूप में नहीं,बल्कि दैनिक बोलचाल में भी प्रयोग करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम का संचालन कक्षा दसवीं की छात्राओं सुषमा यादव एवं ज्योति ने किया। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया।

### सीए भी साइबर ठगों के निशाने पर...सरगुजा पुलिस ने बताए बचाव के तरीके

# 'साइबर जागृति अभियान' के तहत सीए एसोसिएशन में जागरूकता

## शिविर,डिजिटल अरेस्ट,इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और फिशिंग से बचने दिए टिप्स

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ साइबर ठगी के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसी को देखते हुए 'साइबर जागृति अभियान' के तहत सरगुजा पुलिस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के लिए विशेष साइबर जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल ने वित्तीय क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स को साइबर अपराधों से बचाव के महत्वपूर्ण तरीके बताए। कार्यक्रम डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित किया गया। सीए एसोसिएशन ने जागरूकता कार्यक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से प्रोफेशनल्स के साथ आम लोगों को भी साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करने में मदद मिलेगी।

**वित्तीय डेटा की सुरक्षा सबसे जरूरी :** सीएसपी राहुल बंसल ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन बढ़ने के साथ साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। सीए के पास व्यवसायियों और आम नागरिकों से जुड़ा महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा रहता है, इसलिए उनके लिए साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। कार्यशाला में फिशिंग लिंक, फर्जी ई-मेल, स्पूफिंग कॉल, निवेश संबंधी ठगी, डिजिटल अरेस्ट और लोन ऐप स्कैम के तौर-तरीकों की जानकारी दी गई। क्लाइंट्स के संवेदनशील वित्तीय डेटा और पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे सुरक्षा उपाय अपनाने पर जोर दिया गया।

**ठगी होते ही 1930 पर करें शिकायत :** साइबर ठगी होने पर तत्काल कार्रवाई को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने और cybercrime.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साइबर एक्सपर्ट आरक्षक अनुज जायसवाल ने तकनीकी संसाधनों के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव के व्यावहारिक उपाय बताए।

**पुलिस की पहल का स्वागत :** सीए एसोसिएशन के सदस्यों ने सरगुजा पुलिस की पहल की सराहना करते हुए कहा कि वे स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के साथ अपने क्लाइंट्स और आम लोगों को भी सतर्क करेंगे। एसोसिएशन की ओर से डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल से भेंट कर कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ सीए एच.एस. जायसवाल,संयोजक धीरज अग्रवाल सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य,जिले के सीए, नवाबिहान टीम के अजय तिवारी, मंगल पाण्डेय,उप निरीक्षक अभय तिवारी, साइबर सेल प्रभारी एएसआई अजीत मिश्रा,आरक्षक अनुज जायसवाल और राहुल केरकेट्टा उपस्थित रहे।

# अंतिम संस्कार से पहले उठे सवाल,शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे परिजन

### नाबालिग आदिवासी बालिका की फांसी से मौत पर संदेह,दोबारा पोस्टमार्टम की मांग...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी बालिका की फांसी से मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपे जाने के बावजूद परिवार और समाज के लोगों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार देर शाम परिजन शव लेकर अंबिकापुर स्थित आईजी कार्यालय पहुंचे और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की।

मामला प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत करौंधा का है। मृतका बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और करौंधा निवासी श्रवण जायसवाल के घर में रहकर घरेलू काम करती थी। मंगलवार दोपहर खाना खाने के बाद वह कमरे में आराम करने चली गई थी। शाम को कमरे में नहीं दिखने पर घरवालों ने तलाश की तो वह फांसी के फंदे पर लटकी मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया था। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे,इसी दौरान घटना की जानकारी समाज के लोगों को हुई। इसके बाद परिजन और समाज के लोग शव लेकर अंबिकापुर पहुंचे। परिजनों ने घटना को लेकर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मौत की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

## जिला अस्पताल परिसर से दो बाइक चोरी,रिपोर्ट दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला अस्पताल परिसर से दो व्यक्ति की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर निवासी रोहन प्रसाद पिछले चार साल से अंबिकापुर के बौरीपारा में रह रहा है। वह अपने परिचित सामियल किंडो की बाइक क्रमांक सीजी 15 एसी 2067 का करीब तीन साल से उपयोग कर रहा था। 24 अगस्त को रोहन जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती अपने रिश्तेदार से मिलने गया था। सुबह करीब 11.15 बजे उसने बाइक अस्पताल परिसर में खड़ी की और अंदर चला गया। करीब 1 बजे वापस लौटने पर बाइक निर्धारित स्थान से गायब थी। आसपास तलाश करने और लोगों से पूछताछ के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। इसके बाद रोहन ने पुलिस सहायता केंद्र में शिकायत की। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर बाइक चोरी होने की जानकारी सामने आई। पीड़ित ने मणिपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं दूसरी घटना बौरीपारा निवासी संतोष अगरिया 1 सितंबर को अपनी बाइक क्रमांक सीजी 15 ईडी 2753 से जिला अस्पताल में परिचित को ब्लड देने गया था।

# बूम बैरियर गिरा तो 'वीआईपी गुस्सा' टोलकर्मी पर बरसा!

## मंत्री के काफिले की गाड़ी पर गिरा टोल बूम,कर्मचारी हाथ जोड़ता रहा...थप्पड़ पड़ते रहे...वीडियो वायरल...थाने पहुंचा मामला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सरकारी व्यवस्था में आम आदमी को अक्सर नियम-कायदे समझाने वाले वीआईपी काफिले के सामने वही नियम कितने बेबस हो जाते हैं,इसकी तस्वीर लखनपुर के लहपटरा टोल नाके से सामने आई है। मामला इतना भर था कि टोल का बूम बैरियर मंत्री के काफिले की गाड़ी पर गिर गया। इसके बाद गुस्सा इतना बढ़ा कि बैरियर तो बच गया, लेकिन एक टोलकर्मी के गाल जरूर 'वीआईपी प्रोटोकॉल' की मार झेल गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में टोल कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है,जबकि उसके सामने मौजूद व्यक्ति उसे थप्पड़ मारता दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल यह है कि गलती मशीन की थी तो सजा कर्मचारी को किस नियम के तहत दी गई?

**बूम अपने आप गिरा,लेकिन थप्पड़ अपने आप नहीं पड़े :** जानकारी के अनुसार अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर लहपटरा टोल नाके से रात करीब 12:30 बजे महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का काफिला गुजर रहा था। आगे चल रही गाड़ी के निकलने के बाद स्वचालित टोल प्रणाली के तहत बूम बैरियर नीचे आया और पीछे आ रही मंत्री की गाड़ी से टकरा गया। इससे वाहन को नुकसान पहुंचा। बस फिर क्या था–बूम गिरने की खटाक के बाद टोल प्लाजा पर वीआईपी गुस्से की

आवाजें गूंजने लगीं। रिपोर्टों के अनुसार मंत्री के निजी सहायक ओम प्रकाश राजवाड़े पर टोल कर्मचारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट का आरोप है। वीडियो में कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दे रहा है।

**'माफ कर दीजिए साहब'...लेकिन थप्पड़ का हिसाब कौन देगा?** वायरल वीडियो की सबसे परेशान करने वाली तस्वीर यही है कि एक कर्मचारी हाथ जोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है। सामने खड़ा व्यक्ति लगातार थप्पड़ मारता नजर आता है।

**अब सवाल यह नहीं कि बूम बैरियर क्यों गिरा?** सवाल यह भी है कि यदि बूम सिस्टम में तकनीकी या संचालन संबंधी गलती हुई थी तो उसकी जांच कौन करता? टोल कंपनी से जवाब कौन मांगता? नुकसान का आकलन कौन करता? क्या सड़क पर कानून का काम जांच करना है या मौके पर ही 'तुरंत न्याय' कर देना? फॉलो वाहन होता तो शायद बूम भी

'वीआईपी' पहचान लेता! टोल कर्मचारियों की ओर से एक दिलचस्प सफाई सामने आई है। बताया गया कि काफिले में पहले की तरह फॉलो वाहन नहीं था। आगे वाली गाड़ी निकल गई और उसके पीछे मंत्री का वाहन होने की जानकारी टोलकर्मियों को नहीं हो सकी। इसी कारण स्वचालित सिस्टम ने बूम नीचे कर दिया। यानी मामला तकनीक और प्रोटोकॉल के बीच फंस गया।

बूम को क्या पता कि पीछे आने वाली गाड़ी आम आदमी की है या मंत्री की? मशीन ने अपना काम किया–लेकिन मशीन के बाद इंसानों ने जो किया, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं।

**थाने पहुंचा टोलकर्मी,अब पुलिस तय करेगी 'किसका प्रोटोकॉल':** घटना के बाद पीड़ित टोल कर्मचारी महेंद्र राजवाड़े अन्य टोलकर्मियों और ग्रामीणों के साथ लखनपुर थाने पहुंचा और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब गेंद पुलिस के पाले में है। वायरल वीडियो,प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और शिकायत के आधार पर पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि मारपीट किसने की,किस परिस्थिति में की और क्या कानून हाथ में लेने की कोशिश हुई।

**वीआईपी काफिला और आम कर्मचारी...कानून की नजर में फर्क कितना?** यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें मंत्री के काफिले का नाम सामने आया है। हालांकि मंत्री स्वयं मारपीट में शामिल थीं,ऐसा उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं कहा गया है; एक रिपोर्ट के अनुसार वे घटना के दौरान वाहन में ही थीं और बाद में सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव किया। मामले की जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन वायरल वीडियो ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है...अगर टोल का बूम किसी आम आदमी की गाड़ी पर गिरता और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता,तो क्या मामला इतना ही 'छोटा' माना जाता?

लोकतंत्र में पद बड़ा हो सकता है,काफिला बड़ा हो सकता है,गाड़ी महंगी हो सकती है...लेकिन कानून की किताब सबके लिए एक ही होनी चाहिए। अब देखना यह है कि लखनपुर पुलिस इस मामले में बूम बैरियर की तकनीकी जांच करती है या सिर्फ मामले के 'वीआईपी वजन' को देखती है।

***फिलहाल टोल प्लाजा पर एक सवाल हवा में तैर रहा है...बूम गिरने की गलती किसकी थी,यह जांच से पता चलेगा,लेकिन थप्पड़ चलाने का अधिकार आखिर किसने दे दिया?***

# कागजों में हर घर जल, बिजली चट्टान में ढोढ़ी के पानी का सहारा....सीतापुर की पहाड़ी बस्ती में विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों की जिंदगी मुश्किल,स्वच्छ पेयजल के लिए ग्रामीणों ने लगाई गुहार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के दावे कर रही है,लेकिन सीतापुर विकासखंड के ग्राम बिजली चट्टान की पहाड़ी बस्ती में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीजीटी) के परिवार आज भी ढोढ़ी के पानी पर निर्भर हैं। बस्ती में नल-जल की स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण इसी पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने और रोजमर्रा के कामों में कर

रहे हैं। सरकारी योजनाओं में जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंचाने का

लक्ष्य रखा गया है। बावजूद इसके बिजली चट्टान की पहाड़ी बस्ती के परिवारों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ढोढ़ी का पानी भी साफ नहीं है, जिससे गंदा पानी पीने से बीमारी का खतरा बना रहता है। एक ओर शासन-प्रशासन आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा करता है, वहीं बिजली चट्टान की बस्ती में रहने वाले परिवार आज भी पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बस्ती में हैंडपंप या नल-जल योजना के तहत स्थायी व्यवस्था हो जाए तो उन्हें काफी राहत मिलेगी।

**ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार :** बस्ती के अजय राम, सोमार साय, बंधनु राम, सनी राम, घुरसाय,नईहारो बाई, अंजना बाई,मनियारी बाई,धनेश्वर राम, संजय राम,कुंवर साय,दिनेश राम, सीताराम,नान साय और सुखमतिया बाई सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बस्ती में हैंडपंप लगाने अथवा नल-जल योजना से पानी उपलब्ध कराने की मांग की है।

CMYK

# 50 लाख की चोरी का 'चक्रव्यूह'!

## चोर 27 को पकड़े, खरीदार 1 सितंबर को मिला!

- 22 अगस्त की रात टीएमसी स्टोर से चोरी
- 27 अगस्त को 4 आरोपी गिफ्तार, 40 लाख का माल बरामद
- 1 सितंबर को खरीदार सुजीत तामकार गिरफ्तार, 10 लाख का माल बरामद
- अब उठे कई सवाल!

# कोरिया पुलिस का कमाल : चोर 27 को मिले,खरीदार 1 सितंबर को 50 लाख की चोरी का गणित बिल्कुल फिट!

**पहले 40 लाख की बरामदगी,फिर 10 लाख का 'अचानक' प्रकट होना...पुलिस की दूसरी विज्ञप्ति ने खोल दिए कई नए सवाल...**

**40 लाख की पहली बरामदगी के बाद 10 लाख का दूसरा खुलासा,पुलिस की दो प्रेस विज्ञप्तियों ने खड़े किए जांच की टाइमलाइन पर सवाल**

**टीएमसी की 50 लाख की चोरी,चोरों की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद कथित खरीदार क्यों पकड़ा गया?**

**40 लाख का माल पहले मिला, 10 लाख बाद में,कोरिया पुलिस की चोरी की कहानी में 'खरीदार' का लेट एंट्री!**

**चोर पकड़े, माल बरामद...फिर पांच दिन बाद मिला खरीदार! कोरिया पुलिस की कार्रवाई पर सवाल**

**50 लाख की चोरी,40 लाख की बरामदगी और पांच दिन बाद 10 लाख का 'खुलासा'**

**कोरिया पुलिस का '50 लाख वाला गणित': 40 लाख + 10 लाख = पूरा माल बरामद!**

**चोरी खुली या कहानी? पहले चोर,फिर खरीदार...पांच दिन में बदली पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति**

**चोरों से खरीदार तक पुलिस की 'पांच दिन की यात्रा',50 लाख की चोरी में उठे बड़े सवाल**

**'माल पूरा बरामद'...लेकिन खरीदार पांच दिन बाद! कोरिया पुलिस की कहानी में कई अनुत्तरित सवाल**

-रवि सिंह-

**कोरिया,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।** कोरिया पुलिस में चोरी के मामलों का खुलासा भी कभी-कभी चोरी से ज्यादा दिलचस्प हो जाता है,चोरी होती है, एफआईआर दर्ज होती है,साइबर सेल सक्रिय होता है, चोर पकड़े जाते हैं,माल बरामद होता है और फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर बताया जाता है कि पुलिस ने शानदार सफलता हासिल कर ली,जनता भी सोचती है की चलो,मामला खुल गया, लेकिन कुछ मामलों में पुलिस का 'खुलासा' ही नए सवालों का ताला खोल देता है। बता दे की टीएमसी पाण्डोपारा की झिलमिली साइट के स्टोर से हुई लाखों रुपये की चोरी का मामला फिलहाल इसी श्रेणी में खड़ा दिखाई दे रहा है,पुलिस की पहली प्रेस विज्ञप्ति में चार आरोपियों की गिरफ्तारी और करीब 40 लाख रुपये के चोरी के पार्ट्स की बरामदगी का दावा किया गया, इसके बाद 1 सितंबर को दूसरी विज्ञप्ति आई,जिसमें कथित खरीदार सुजीत ताम्रकार की गिरफ्तारी और उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपये के पार्ट्स बरामद करने की बात कही गई,इसके बाद पुलिस ने कहा की चोरी हुआ पूरा सामान बरामद कर लिया गया, गणित देखिए की 40 लाख और 10 लाख मिलाकर 50 लाख,हिसाब तो बिल्कुल दुरुस्त,लेकिन पत्रकारिता का काम सिर्फ जोड़ना नहीं है,यह पूछना भी है कि ये रकम किस रास्ते से आई, किसके पास गई और पुलिस को किस मोड़ पर कौन मिला?

**पहली विज्ञप्ति में खरीदार की कहानी,दूसरी में खरीदार की गिरफ्तारी**

यहीं से इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, पुलिस की पहली विज्ञप्ति में चोरी का सामान कबाड़ी को बेचने की बात कही गई है। यानी जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी कि चोरी का माल सिर्फ चोरों के पास नहीं रहा, बल्कि उसे आगे बेचा गया,तो सवाल है–यदि चोरी का माल बेचने वाले और खरीदने वाले की कड़ी 27 अगस्त की जांच में सामने आ गई थी,तो कथित खरीदार की गिरफ्तारी 1 सितंबर को क्यों हुई? 27 अगस्त से 1 सितंबर तक पांच दिन का अंतर है,क्या इन पांच दिनों में पुलिस कथित खरीदार की तलाश कर रही थी? क्या वह फरार था? क्या पुलिस को उसका नाम बाद में पता चला? क्या उसके ठिकाने की निगरानी की गई? क्या उसके मोबाइल और वाहन की जांच की गई? या फिर कहानी में खरीदार का अध्याय ही बाद में जोड़ा गया? इन सवालों का जवाब पुलिस की दूसरी विज्ञप्ति नहीं देती,दूसरी विज्ञप्ति सिर्फ यह बताती है कि 1 सितंबर को सुजीत ताम्रकार को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके पेश करने पर करीब 10 लाख रुपये के पार्ट्स बरामद हुए।

**22 अगस्त की रात चोरी,24 अगस्त को रिपोर्ट और 27 अगस्त को चोर गिरफ्त में**–पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 22 अगस्त 2026 की रात करीब 1:34 बजे टीएमसी कंपनी की झिलमिली साइट स्थित स्टोर में चोरी हुई,यहां कोयला उत्खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के महंगे पार्ट्स रखे थे,जिनमें तांबा,पीतल और कांसा आदि धातुओं का इस्तेमाल होता है,24 अगस्त को कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पुलिस को शिकायत दी, चोरी की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई और पटना थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू हुई, इसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। साइबर सेल को लगाया गया,संदिग्धों से पूछताछ हुई और पुलिस के अनुसार चोरी की पूरी कड़ी सामने आने लगी,27 अगस्त को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने दावा किया कि आरोपी 9-10 लोगों के समूह में चोरी करने पहुंचे थे, स्टोर की छत की सीट हटाई गई, मशीनों के महंगे पार्ट्स निकाले गए, चोरी का सामान पहले जंगल में छिपाया गया और बाद में उसे बेच दिया गया, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर करीब 40 लाख रुपये का सामान बरामद हुआ,यानी पुलिस की पहली कहानी में चोर भी मिल गए और माल भी,लेकिन एक चीज अभी बाकी थी–कथित खरीदार।

**40 लाख पहले,10 लाख बाद में...चोरी का 'किश्तों वाला खुलासा'**– पुलिस की दोनों विज्ञप्तियों को साथ रखिए तो मामला कुछ यूं बनता है पहली किश्त में चार आरोपी गिरफ्तार, 40 लाख का माल बरामद,दूसरी किश्त में कथित खरीदार गिरफ्तार, 10 लाख का माल बरामद, अंतिम घोषणा में चोरी का पूरा सामान बरामद,ऐसा लगता है जैसे चोरी का खुलासा भी किसी वेब सीरीज की तरह एपिसोड में रिलीज हुआ हो,पहले एपिसोड में चोर, दूसरे में खरीदार,और दर्शकों के लिए बोनस सवाल–बाकी किरदार कौन हैं? व्यंग्य अपनी जगह है,लेकिन इस अंतर की जांच गंभीरता से होना जरूरी है,क्योंकि किसी भी आपराधिक मामले में बरामदगी की तारीख,स्थान,व्यक्ति और परिस्थितियां केस की महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं।

**50 लाख या उससे अधिक? रकम का सवाल भी कम दिलचस्प नहीं**– इस मामले में एक और सवाल चोरी की वास्तविक कीमत को लेकर है,कंपनी की शिकायत में करीब 50 लाख रुपये की चोरी बताई गई,पहली प्रेस विज्ञप्ति में करीब 40 लाख रुपये का सामान बरामद होने की बात कही गई,दूसरी में करीब 10 लाख रुपये की बरामदगी बताई गई,लेकिन स्थानीय स्तर पर चोरी की रकम को लेकर 50 लाख से अधिक,यहां तक कि उससे कहीं ज्यादा होने की चर्चाएं भी हैं,अब सवाल है–आधिकारिक मूल्यांकन क्या है? क्या चोरी गए प्रत्येक पार्ट की सूची तैयार हुई? क्या टीएमसी के अधिकृत अधिकारी ने बरामद सामान की पहचान की? क्या प्रत्येक पार्ट का मूल्य कंपनी के रिकॉर्ड से मिलाया गया? क्या 40 लाख और 10 लाख की कीमत का आधार समान है? और यदि कंपनी की वास्तविक क्षति 50 लाख से अधिक है तो पुलिस की विज्ञप्तियों में 50 लाख का आंकड़ा ही क्यों प्रमुख है? यह सवाल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि बरामदगी और मूल्यांकन की पारदर्शिता के लिए है।

**अब कहानी में सुजीत ताम्रकार और उसके बेटे का अध्याय**– मामले में कथित खरीदार के रूप में सुजीत ताम्रकार का नाम सामने आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है,यहां से जांच का अगला स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या उसकी भूमिका अकेले तक सीमित थी? स्थानीय सूत्रों के हवाले से उसके बेटे की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं,यह दावा भी सामने आया है कि चोरी के सामान की आवाजाही में एक मारुति ईको वाहन का इस्तेमाल हुआ था,लेकिन पुलिस की उपलब्ध दोनों विज्ञप्तियों में उस वाहन की बरामदगी या सुजीत के बेटे की गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं है,तो फिर सवाल यह है अगर वाहन की जानकारी जांच में आई थी,तो पुलिस उस वाहन तक पहुंची या नहीं? वाहन किसके नाम पर है? घटना की रात उसकी लोकेशन क्या थी? क्या सीसीटीवी फुटेज में वाहन दिखाई देता है? क्या उसमें चोरी का सामान ले जाया गया था? यदि हां,तो उसका ड्राइवर कौन था? और यदि पुलिस को इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं, तो क्या मामला वास्तव में पूरी तरह खुल गया है?

**सड़क किनारे मिला बताया जा रहा माल...सबसे बड़ा रहस्य**–इस पूरे प्रकरण में एक और दावा सामने आया है, जिसे लेकर विभागीय स्तर पर जांच की जरूरत महसूस होती है, सूत्रों के अनुसार चोरी के कुछ सामान को पटना से कटगोड़ी/मुरमा की ओर जाने वाले मार्ग पर फेंके जाने की बात कही जा रही है,दावा है कि इस सामान की सूचना एक पुलिसकर्मी तक पहुंची और उसके बाद पटना पुलिस को जानकारी देकर सामान बरामद कराया गया,यह दावा फिलहाल स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं है और पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में भी सामान के सड़क किनारे लावारिस हालत में मिलने का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो सवाल बेहद सीधा है की उस सामान की जानकारी सबसे पहले संबंधित पुलिसकर्मी को कैसे मिली? किसने फोन किया? किस नंबर से फोन आया? किस समय सूचना दी गई? सूचना देने वाले को कैसे पता था कि वहां चोरी का सामान पड़ा है? क्या बरामदगी स्थल का पंचनामा बनाया गया? क्या वहां सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था? क्या किसी वाहन की पहचान हुई? और क्या उस बरामदगी को केस डायरी में उसी रूप में दर्ज किया गया है? क्योंकि 'आरोपी के कब्जे से बरामद' और 'सड़क किनारे लावारिस मिला'–दोनों परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं।

**पहली विज्ञप्ति बनाम दूसरी विज्ञप्ति**

| बिंदु | पहली प्रेस विज्ञप्ति | दूसरी प्रेस विज्ञप्ति |
|---|---|---|
| चोरी | करीब 50 लाख | करीब 50 लाख |
| गिरफ्तारी | 4 आरोपी | कथित खरीदार सुजीत ताम्रकार |
| बरामदगी | करीब 40 लाख | करीब 10 लाख |
| तारीख | 27 अगस्त | 1 सितंबर |
| स्थिति | शेष माल/आरोपियों की तलाश | पूरा माल बरामद |
| बड़ा सवाल | खरीदार कौन? | खरीदार पहले क्यों नहीं? |

**पांडेय जी तक सूचना पहले कैसे पहुंची?**– यही वह बिंदु है जहां स्थानीय चर्चाओं में कोरिया पुलिस से जुड़े प्रधान आरक्षक पांडेय का नाम सामने आता है,आरोप है कि कथित सड़क किनारे पड़े सामान की जानकारी उन्हें मिली और फिर उन्होंने पटना पुलिस को इसकी सूचना दी,यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो सवाल बनता है पांडेय को ही यह सूचना क्यों मिली? और उनसे पहले पुलिस को जानकारी क्यों नहीं थी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि चोरी के सामान को किसी आरोपी अथवा उसके सहयोगी ने रास्ते में फेंका था,तो उसके बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति खुद जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है,इसलिए सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके पुलिसकर्मी तक पहुंचने की कहानी जांच का हिस्सा होनी चाहिए।

**'सुपर कॉप' और 'मायावी' की चर्चा ?**–इस मामले के साथ एक और पुलिसकर्मी का नाम स्थानीय चर्चाओं में लिया जा रहा है,जो वर्तमान में पड़ोसी एमसीबी जिले में पदस्थ बताया जाता है,स्थानीय स्तर पर उसके लिए 'सुपर कॉप', 'मायावी' जैसे उपनाम इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है,आरोप यह भी लगाए जाते रहे हैं कि जिला छोड़ने के बाद भी कोरिया में उसका प्रभाव और संपर्क बना हुआ है,यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी आरोप और चर्चाएं हैं, स्थापित तथ्य नहीं, किसी पुलिसकर्मी पर अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने, आरोपी को बचाने या लेनदेन करने जैसे आरोप गंभीर हैं और इनकी पुष्टि केवल स्वतंत्र जांच, विभागीय रिकॉर्ड या अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से ही हो सकती है, लेकिन यदि ऐसे आरोप बार-बार उठ रहे हैं तो उन्हें जांच के दायरे में लाना विभाग के हित में ही होगा।

**तिवारी जी एमसीबी में...फिर कोरिया में मौजूदगी क्यों?**–सबसे बड़ा सवाल संबंधित पुलिसकर्मी की कोरिया जिले में कथित मौजूदगी को लेकर है,यदि वह वर्तमान में एमसीबी जिले में पदस्थ हैं तो यह पता लगाया जा सकता है कि चोरी की घटना और उसके बाद की जांच के दौरान वह कोरिया जिले में कब-कब आए, इसके लिए किसी विशेष जासूसी की आवश्यकता नहीं,सीसीटीवी देखिए, मोबाइल लोकेशन देखिए,वाहन की आवाजाही देखिए,कॉल डिटेल देखिए,यदि वे नहीं आए तो आरोप खत्म, यदि आए तो आने का कारण दर्ज होगा,और यदि उनका इस केस से कोई संबंध नहीं था तो जांच उसी तथ्य को साबित कर देगी।

**'लाल महल' की चर्चा भी सीसीटीवी में खोजी जा सकती है**– स्थानीय लोगों के हवाले से यह भी चर्चा है कि संबंधित पुलिसकर्मी का बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में आना-जाना बना रहता है और एक खास स्थान,जिसे स्थानीय बोलचाल में 'लाल महल' कहा जा रहा है,से उसके संपर्क की चर्चा होती है,इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है,लेकिन यदि सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं तो मामला सरल है,तारीख निकालिए, फुटेज देखिए, व्यक्ति की पहचान कीजिए, वाहन देखिए,अगर कुछ नहीं है तो चर्चा खत्म,अगर फुटेज में मौजूदगी है तो फिर अगला सवाल होगा–किससे मिलने आए थे और क्यों? यानी इस पूरे मामले में आरोपों का जवाब भी आरोप से नहीं,रिकॉर्ड से दिया जा सकता है।

**क्या पुलिस ने पूरी 'चेन' पकड़ी या सिर्फ चोरी का माल?**– चोरी के मामले का खुलासा केवल सामान बरामद होने से पूरा नहीं माना जाना चाहिए,असली सवाल पूरी श्रृंखला का है स्टोर से सामान किसने निकाला? किसने वाहन में रखा? किसने रास्ता बताया? किसने जंगल में छिपाया? किसने खरीदा? किसने आगे बेचा? किसने भुगतान किया? किसने सामान इधर-उधर किया? किसने सड़क किनारे फेंका? और किसे पहले से पता था कि सामान कहां है? यदि पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़ देती है तो मामला वास्तव में मजबूत खुलासा कहलाएगा।

**वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ सीधी मांग...**

- पहला–पूरी टाइमलाइन सार्वजनिक हो 22 अगस्त से 1 सितंबर तक पुलिस ने कब-कब क्या कार्रवाई की?
- दूसरा–कथित खरीदार तक पहुंचने की कहानी बताई जाए सुजीत ताम्रकार का नाम पुलिस को कब पता चला?
- तीसरा–सीसीटीवी जांच हो घटनास्थल से लेकर माल के संभावित परिवहन मार्ग तक।
- चौथा–वाहनों की जांच हो किस वाहन से चोरी का माल गया?
- पांचवां–कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच हो चोरों और कथित खरीदार के बीच संपर्क था या नहीं?
- छठा–पुलिसकर्मियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो क्या किसी दूसरे जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी ने इस केस में हस्तक्षेप किया?
- सातवां–बरामद माल का स्वतंत्र मूल्यांकन हो 40 लाख और 10 लाख की कीमत किस आधार पर तय हुई?

# सरगुजा में पहाड़ी कोरवा-पंडो में मिला लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस का संक्रमण

-संवाददाता-
**अम्बिकापुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।**

सरगुजा के आदिवासी बहुल इलाकों में पहाड़ी कोरवा और पंडो जनजाति के लोगों में लेप्टोस्पाइरा (रैट फीवर) और स्क्रब टाइफस का संक्रमण सामने आया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार बुखार के मामलों की जांच के दौरान दोनों संक्रमणों की पुष्टि हुई है। इस साल अब तक लेप्टोस्पाइरा के 50 और स्क्रब टाइफस के 22 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि, उपचार के बाद सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. पंकज टेभूलकर के अनुसार, जिन मरीजों का पांच दिन बाद भी बुखार नहीं उतरता है, उनके ब्लड सैंपल की जांच कराई जाती है। ऐसे मरीजों में लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस की आशंका होने पर एलाइजा टेस्ट कराया जा रहा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तत्काल मामलों की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की संयुक्त टीम संक्रमण को लेकर रिसर्च कर रही है। टीम प्रभावित गांवों में भी पहुंचेगी। यहां मरीजों की जांच के साथ आवश्यक सैंपल लिए जाएंगे, ताकि संक्रमण के कारणों और इसके फैलाव की स्थिति का पता लगाया जा सके। लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस दोनों संक्रमणों का समय पर पता चलना और उपचार शुरू होना जरूरी है। देरी होने पर संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है।

# ग्रामीणों की सतर्कता से खुली मवेशी तस्करी की पोल,तीन आरोपी गिरफ्तार

**शंकरगढ़ पुलिस की कार्रवाई,क्रूरता से बांधे 3 मवेशी बरामद,तस्करी में इस्तेमाल अर्टिगा जब्त**

-संवाददाता-
**शंकरगढ़,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।**

मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ शंकरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल अर्टिगा कार क्रमांक CG 12-BF-6072 जब्त की है। वहीं मौके से क्रूरतापूर्वक हाथ-पैर और गर्दन बांधे गए तीन मवेशियों को भी बरामद किया गया।

**पिकअप में मवेशी लोड करते देख ग्रामीण ने दी सूचना :** पुलिस के अनुसार मामला जसवंतपुर के बाघु टोंगरी के पास का है। ग्रामीण हमेंद्र कुमार ने सूचना दी कि कुछ लोग पिकअप और कार खड़ी कर मवेशियों को जबरन पिकअप में लोड कर रहे हैं। ग्रामीणों की आहट मिलते ही पिकअप और अर्टिगा के चालक वाहन लेकर भागने लगे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को पकड़ लिया। मौके से तीन मवेशी भी बरामद किए गए, जिन्हें कथित रूप से हाथ-पैर और गर्दन बांधकर ले जाने की तैयारी थी।

**पूछताछ में झारखंड तक तस्करी का खुलासा :** पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि सीतापुर और आसपास के पहाड़ी इलाकों से मवेशी एकत्र कर पिकअप के माध्यम से झारखंड के बूचड़खानों तक ले जाने की योजना थी। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

**गिरफ्तार आरोपी—** कौशर अंसारी (32), निवासी मानपुर, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड मिल्लत अंसारी (27), निवासी मानपुर, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड, सोनू उर्फ नुरूल हसन (25), निवासी मुरका, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर।

# खेत में नहीं बढ़ी जमीन, कागज पर रकबा

# बढ़ा और बिक गया 4728.80 क्विंटल धान!

## दो साल...एक जैसा खेल? शिवप्रसादनगर में कम रकबे पर ज्यादा पंजीयन और हजारों क्विंटल धान खरीदी का आरोप

- 2023-24 में समिति प्रबंधक सोहराब अंसारी पर सवाल, 2024-25 में सोहराब अंसारी और साधना कुशवाहा की भूमिका घेरे में...
- 23 किसानों के नाम पर 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे और 4728.80 क्विंटल धान बिक्री के दावे ने खोली व्यवस्था की पोल
- 23 किसानों की वास्तविक 20.94 हेक्टेयर जमीन के मुकाबले 88.27 हेक्टेयर रकबा दर्ज करने का आरोप...
- 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे पर सवाल–2023-24 और 2024-25 की खरीदी की जांच की मांग...
- पहले ओड़गी ब्लॉक के किसानों का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के किसानों के नाम जोड़ने का आरोप,फिर उसी आधार पर धान खरीदी
- खबरें और शिकायतें सामने आने के बाद भी कार्रवाई पर सवाल...क्या कागजों में बढ़ता रहा खेत और गोदाम में आती रही फसल...
- शिवप्रसादनगर में रकबा बढ़ा,धान बिका... अब एफआईआर और जांच का इंतजार
- दो साल, एक जैसा खेल? रकबा बढ़ाने के आरोपों से घिरी शिवप्रसादनगर धान खरीदी
- कागज पर खेत बढ़े, धान के आंकड़े दौड़े–शिवप्रसादनगर समिति पर गंभीर सवाल
- खबरें छपीं, दस्तावेज सामने आए...फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं...शिवप्रसादनगर के रकबा कांड पर सवाल

सूरजपुर में महाघोटाले की गूंज...7.7 एकड़ जमीन ट्रांसफर और 67.33 हेक्टेयर फर्जी रकबा का खेल
जमीन,धान और बैंकिंग का जालः शिवप्रसादनगर समिति से जुड़ा बड़ा खुलासा

रकबा बढ़ा, धान बिका... खबरें छपी, फिर भी प्रशासन की आंखें बंद!
शिवप्रसादनगर में रकबा बढ़ा,धान बिका और खबरें भी छपी...फिर भी प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुलीं?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक की शिवप्रसादनगर धान खरीदी समिति एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है,इस बार मामला सिर्फ एक किसान,एक सीजन या किसी मामूली रिकॉर्ड त्रुटि तक सीमित नहीं बताया जा रहा,सामने आई शिकायतों और उपलब्ध विवरण के अनुसार धान खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25, लगातार दो खरीदी वर्षों में किसानों के वास्तविक रकबे से अधिक भूमि का पंजीयन कर उसी आधार पर हजारों क्विंटल धान खरीदी किए जाने का आरोप है। आरोप है कि वर्ष 2023-24 में समिति प्रबंधक/धान खरीदी प्रभारी सोहराब अंसारी द्वारा ओड़गी ब्लॉक के किसानों के रकबे को शिवप्रसादनगर समिति के अंतर्गत पंजीकृत किसानों के नाम पर वास्तविक रकबे से अधिक दर्ज कराया गया और उसके आधार पर धान खरीदी की गई, इसके बाद वर्ष 2024-25 में भी कथित रूप से यही प्रक्रिया दोहराई गई,इस वर्ष समिति प्रबंधक सोहराब अंसारी और धान खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि ओड़गी ब्लॉक के किसानों की जमीन का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के पंजीकृत किसानों के नाम पर वास्तविक रकबे से अधिक दर्ज कराया गया और फिर उसी आधार पर हजारों क्विंटल धान खरीदी की गई, इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण निष्पक्ष जांच से ही होगा, लेकिन यदि उपलब्ध आंकड़े और रिकॉर्ड जांच में सही पाए जाते हैं तो मामला किसान पंजीयन से लेकर धान खरीदी और सरकारी भुगतान तक पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग करता है।

### 2023-24 में शुरू हुआ मामला या तभी से चल रहा था खेल?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल वर्ष 2023-24 से जुड़ा है,आरोप है कि उस खरीदी वर्ष में समिति प्रबंधक/धान खरीदी प्रभारी सोहराब अंसारी ने ऐसे किसानों के नाम पर अधिक रकबा पंजीकृत कराया जिनके वास्तविक खेत का रकबा कम था,यानी किसान के पास जमीन कम और सरकारी रिकॉर्ड में खेती का क्षेत्र अधिक,यदि ऐसा हुआ तो सवाल केवल यह नहीं कि पंजीयन किसने किया। सवाल यह है कि रकबा सत्यापन किसने किया? किसान के पास जितनी जमीन थी, उसका रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए,ऐसे में पंजीयन के समय वास्तविक रकबे और दर्ज रकबे का मिलान क्यों नहीं हुआ? क्या किसान पंजीयन के समय दस्तावेजों की जांच हुई? क्या समिति ने राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया? क्या संबंधित अधिकारी ने सत्यापन किया? यदि किया तो कथित रूप से अधिक रकबा दर्ज कैसे हो गया? और यदि सत्यापन नहीं किया गया तो फिर इतने बड़े पैमाने पर धान खरीदी किस आधार पर हुई?

### 2024-25 में फिर वही कहानी, इस बार साधना की भूमिका भी सवालों में-

यदि वर्ष 2023-24 का मामला केवल रिकॉर्ड की गलती थी तो अगले खरीदी वर्ष में वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि वर्ष 2024-25 में भी अधिक रकबा दर्ज कर धान खरीदी की गई, इस बार शिकायत में समिति प्रबंधक सोहराब अंसारी के साथ धान खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, आरोप है कि दोनों की कथित मिलीभगत से ओड़गी ब्लॉक के किसानों का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के पंजीकृत किसानों के नाम पर जोड़ा गया और वास्तविक रकबे से अधिक पंजीयन कराकर धान खरीदी की गई, यह आरोप गंभीर है और इसकी पुष्टि के लिए दोनों खरीदी वर्षों के किसानवार रिकॉर्ड का मिलान आवश्यक है, एक साल की गलती को चूक कहा जा सकता है, लेकिन दो साल लगातार एक जैसे आरोप सामने आएं तो उसे केवल संयोग मानकर छोड़ देना भी जांच से बचने का रास्ता हो सकता है।

**67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा—कागजों में खेत का विस्तार?-** वर्ष 2024-25 से जुड़े उपलब्ध विवरण में 23 किसानों के नाम पर वास्तविक और पंजीकृत रकबे के बीच बड़ा अंतर बताया गया है।

**आंकड़ों के अनुसार-** यानी जहां वास्तविक रकबा 20.94 हेक्टेयर बताया जा रहा है, वहीं पंजीयन में यह आंकड़ा 88.27 हेक्टेयर तक पहुंचने का दावा है, यहां व्यंग्यात्मक सवाल उठना स्वाभाविक है खेत की मेड़ जमीन पर नहीं बढ़ी, लेकिन कागज पर 67.33 हेक्टेयर कैसे बढ़ गई? और अगर कागज पर रकबा बढ़ा तो उसके साथ 4728.80 क्विंटल धान भी कैसे जुड़ गया? यही वह बिंदु है जहां मामला साधारण पंजीयन त्रुटि से आगे बढ़कर गंभीर जांच की मांग करता है।

**0.36 हेक्टेयर जमीन और 441.20 क्विंटल धान...रिकॉर्ड क्या कहता है?-** उपलब्ध तालिका में कई ऐसे उदाहरण बताए गए हैं जहां वास्तविक रकबा बेहद कम है लेकिन पंजीयन और धान बिक्री काफी अधिक दिखाई गई है,मसलन विजय कुमार के नाम 0.36 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 4.66 हेक्टेयर पंजीयन और 441.20 क्विंटल धान बिक्री का विवरण दिया गया है, संताबाई के मामले में 0.45 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 6.76 हेक्टेयर पंजीयन और 366.40 क्विंटल धान बिक्री बताई गई है,शिवनाथ के नाम 0.54 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 5.95 हेक्टेयर पंजीयन और 419.60 क्विंटल धान बिक्री का दावा है, वहीं रामसाय के नाम 0.84 हेक्टेयर वास्तविक रकबे के मुकाबले 4.36 हेक्टेयर पंजीयन और 404.40 क्विंटल धान बिक्री बताई गई है, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। लेकिन यदि रिकॉर्ड में यही स्थिति है तो जांच का सवाल बेहद गंभीर हो जाता है।

**आखिर अतिरिक्त रकबा आया कहां से?-** यही पूरे मामले का मूल प्रश्न है, किसान के पास यदि 0.36 हेक्टेयर जमीन है तो उसके नाम 4.66 हेक्टेयर का पंजीयन किस आधार पर हुआ? यदि 0.45 हेक्टेयर जमीन है तो 6.76 हेक्टेयर कैसे दर्ज हुआ? क्या अतिरिक्त रकबा किसी दूसरे किसान की जमीन से आया? क्या ओड़गी ब्लॉक के किसी किसान का रकबा शिवप्रसादनगर समिति के किसान के नाम जोड़ दिया गया? क्या ऑनलाइन पंजीयन में किसी स्तर पर संशोधन किया गया? क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी के लॉगिन से रकबा बदला गया? इन सवालों का जवाब किसानवार पंजीयन रिकॉर्ड और पोर्टल के डिजिटल लॉग से मिल सकता है।

**धान खरीदी का सबसे बड़ा सवाल...फसल आई कहां से?-** धान खरीदी का रिकॉर्ड केवल रकबे से नहीं जुड़ा होता। फसल का वास्तविक उत्पादन भी जांच का हिस्सा होना चाहिए,यदि 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा दर्ज किया गया और उसके आधार पर 4728.80 क्विंटल धान खरीदा गया तो जांच में यह भी देखना होगा कि क्या वह धान वास्तव में उन्हीं किसानों की जमीन पर पैदा हुआ था? यदि हां, तो खेत कहां है? यदि नहीं,तो धान किस खेत से आया? क्या दूसरे किसानों की फसल किसी अन्य किसान के नाम पर बेची गई? क्या भुगतान उन्हीं खातों में गया जिनके नाम पर धान खरीदा गया? इन सवालों के जवाब से पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है।

**जमीन हस्तांतरण का दूसरा अध्याय-** इस मामले से जुड़ी शिकायतों में ग्राम सोनपुर,तहसील भैयाथान की लगभग 3.13 हेक्टेयर यानी 7.7 एकड़ कृषि भूमि का मामला भी उठाया गया है, बताया गया है कि यह जमीन पूर्व में जरीफुल्ला के नाम दर्ज थी और बाद में हदीस मोहम्मद, रिजवान अंसारी और साधना कुशवाहा के नाम दर्ज होने की बात सामने आई,यदि यह राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है तो जमीन हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया की जांच आवश्यक होगी, विशेष रूप से यह देखा जाना चाहिए कि जमीन के हस्तांतरण के समय उस पर कोई ऋण या बंधक था अथवा नहीं।

**तीन बैंकों के ऋण का सवाल-** शिकायत में संबंधित भूमि पर ॥छत्तीसगढ़ बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से ऋण होने का उल्लेख किया गया है,यदि भूमि पर ऋण लंबित था तो सवाल उठता है कि रजिस्ट्री से पहले संबंधित बैंक की एनओसी ली गई थी या नहीं, यदि एनओसी ली गई थी तो उसका रिकॉर्ड क्या है? यदि ऋण चुका दिया गया था तो भुगतान का प्रमाण क्या है? यदि बंधक हटाया गया था तो राजस्व रिकॉर्ड में उसका उल्लेख कब हुआ? इन सवालों की जांच के बिना भूमि हस्तांतरण की पूरी कहानी अधूरी रहेगी।

**पहले भी खबरें प्रकाशित हुईं,फिर कार्रवाई कहां है?-** इस मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिवप्रसादनगर समिति से जुड़े आरोपों को लेकर पहले भी कई बार समाचार प्रकाशित हो चुके हैं,रकबे के आंकड़े सामने आए, धान खरीदी पर सवाल उठे, जमीन हस्तांतरण का मुद्दा उठा,बैंक ऋण की स्थिति पर सवाल उठे, फिर भी यदि अब तक कोई निर्णायक प्रशासनिक कार्रवाई सामने नहीं आई है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है,यदि खबरों में लगाए गए आरोप गलत हैं तो प्रशासन को रिकॉर्ड के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, यदि आरोप गंभीर हैं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन न खबर को मानना,न आरोप को खारिज करना और न जांच का स्पष्ट परिणाम बताना–यह तीसरी स्थिति जनता के संदेह को और मजबूत करती है,व्यंग्य में कहें तो शायद फाइल भी सोच रही होगी...'पहले धान का मौसम खत्म हो जाए, फिर मेरी जांच होगी।

### क्या प्रशासन ने आंखें मूंद लीं?

किसी खबर में आरोप प्रकाशित होना अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करता, लेकिन जब मामला सरकारी धान खरीदी,किसानों के रकबे और हजारों क्विंटल धान से जुड़ा हो तो प्रशासन का दायित्व है कि वह तथ्य जांचे, यदि 2023-24 और 2024-25 दोनों वर्षों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो दोनों को सामने रखकर तुलना करना मुश्किल काम नहीं है, किसान का वास्तविक रकबा, पंजीकृत रकबा, धान खरीदी, भुगतान, इन चार आंकड़ों का मिलान कर दिया जाए तो पूरा मामला काफी हद तक स्पष्ट हो सकता है।

### क्या दो वर्षों में एक ही पैटर्न दोहराया गया?

यही सबसे महत्वपूर्ण जांच बिंदु है, यदि 2023-24 में अधिक रकबा दर्ज हुआ और उसी आधार पर अधिक धान खरीदा गया,फिर 2024-25 में भी वही तरीका अपनाया गया, तो जांच को यह देखना होगा कि क्या दोनों वर्षों में एक ही किसान,एक ही जमीन, एक ही लॉगिन,एक ही प्रक्रिया या एक ही स्तर के अधिकारी/कर्मचारी जुड़े हुए थे,यदि ऐसा पैटर्न सामने आता है तो मामला और गंभीर हो सकता है।

### अब जांच केवल समिति की नहीं, पूरे सिस्टम की होनी चाहिए..

इस मामले में केवल समिति प्रबंधक या खरीदी प्रभारी की भूमिका देखना पर्याप्त नहीं होगा,जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि किसान पंजीयन किसने किया? रकबा किसने सत्यापित किया? संशोधन किसने किया? किस अधिकारी ने पंजीयन अनुमोदित किया? धान खरीदी किस आधार पर स्वीकार की गई? खरीदी के बाद भुगतान किस खाते में गया? क्या किसी दूसरे किसान का रकबा किसी अन्य किसान के नाम दर्ज हुआ? क्या दोनों खरीदी वर्षों में समान पैटर्न दिखाई देता है? यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी उसी स्तर पर तय होनी चाहिए।

### धान का हिसाब होगा या फाइल फिर सो जाएगी?

शिवप्रसादनगर समिति का यह मामला अब सिर्फ यह सवाल नहीं रह गया है कि किस किसान ने कितना धान बेचा,अब सवाल यह है कि किसान के पास जमीन कितनी थी? पंजीयन में जमीन कितनी दिखाई गई? उस अतिरिक्त रकबे पर धान कितना खरीदा गया? उसकी रकम किसे मिली? और सबसे अहम—दो खरीदी वर्षों में कथित रूप से एक जैसी प्रक्रिया कैसे दोहराई गई? यदि वर्ष 2023-24 में सोहराब अंसारी की भूमिका पर आरोप हैं और वर्ष 2024-25 में सोहराब अंसारी के साथ साधना कुशवाहा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं,तो दोनों वर्षों की पूरी फाइल सामने रखकर जांच करना ही सबसे उचित रास्ता होगा,क्योंकि खेत में जितनी जमीन है,उससे ज्यादा जमीन कागज पर उग आए और फिर उसी कागजी जमीन से हजारों क्विंटल धान भी पैदा हो जाए—तो इसे खेती का चमत्कार कहें या रिकॉर्ड का खेल,यह जांच के बाद ही तय होगा,लेकिन एक बात तय है की जब 23 किसानों के नाम, 67.33 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा और 4728.80 क्विंटल धान का आंकड़ा सामने हो, तब फाइल बंद करने से सवाल बंद नहीं होंगे,अब प्रशासन को तय करना है कि वह इस मामले का वास्तविक हिसाब करेगा या फिर खबरें प्रकाशित होती रहेंगी,शिकायतें जाती रहेंगी और फाइल किसी सरकारी अलमारी में बैठकर अगली धान खरीदी का इंतजार करती रहेगी।

CMYK

# बारिश आई, व्यवस्था बह गई!

## सूरजपुर में सड़क बनी नदी, अस्पताल बना तालाब और नालियां बनीं कचरे का घर

# हर साल बारिश से पहले सफाई के दावे...बारिश आते ही जलभराव की वही पुरानी कहानी,जनता पूछ रही-आखिर पानी निकलेगा कब?

## सूरजपुर में बारिश का 'विकास मॉडल'...सड़क पर नदी...अस्पताल में तालाब और नालियों में कचरा

**नाली बनी,सफाई भूली, बारिश आई तो सूरजपुर की सड़कें बन गईं जलमार्ग**

**बारिश ने उतारा विकास का मुखौटा, सूरजपुर में सड़क पर पानी और व्यवस्था बेपानी**

**सूरजपुर में मानसून की मार,नालियां जाम,सड़कें जलमग्न,जनता परेशान**

**कागज पर नालियां,सड़क पर दरिया,बारिश में बेनकाब हुई सूरजपुर की व्यवस्था**

**बारिश आई और व्यवस्था बह गई! सूरजपुर में सड़क बनी नदी, निकासी व्यवस्था हुई फेल**

**'वोट लो और भूल जाओ' से आगे बढ़ा सूरजपुर, बारिश में जनता ढूंढ रही सूखी सड़क**

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर शहर में बारिश कोई नई मेहमान नहीं है, लेकिन हर साल बारिश आते ही शहर की व्यवस्था जिस तरह घुटनों के बल बैठ जाती है, वह जरूर नई कहानी बन जाती है,कुछ दिनों से हो रही बारिश ने एक बार फिर नगर की बुनियादी व्यवस्थाओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया है,कहीं सड़क पर पानी का समंदर है तो कहीं पुराना अस्पताल तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे पर हालात ऐसे कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बारिश ने शहर को नहीं,बल्कि शहर की व्यवस्था को धो दिया है, फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश के पानी के साथ कचरा और गंदगी भी बहनी चाहिए थी, लेकिन नालियां पहले ही जाम हैं, इसलिए पानी ने सड़क को ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया।

### नाली बनी है, मगर पानी जाना मना है!-

सूरजपुर में जल निकासी के लिए सड़क किनारे नालियां बनाई गई हैं, कागज पर यह व्यवस्था शायद पूरी तरह दुरुस्त होगी, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और है, कई स्थानों पर नालियों में कचरा जमा है, कहीं नालियां अवरुद्ध हैं तो कहीं पानी के बहाव का रास्ता ही बंद नजर आता है, अब सवाल यह है कि जब नाली में पानी ही नहीं जाएगा तो नाली आखिर किस काम की? शायद नगर की व्यवस्था का नया फार्मूला यही है–नाली बनाओ, उसकी सफाई भूल जाओ और बारिश होने पर सड़क को नाला घोषित कर दो, हर साल बारिश से पहले नालियों की सफाई की जरूरत होती है, लेकिन यदि सफाई समय पर नहीं होगी तो बारिश का पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, इस बार भी पानी ने रास्ता चुन लिया है और वह रास्ता सड़कों से होकर गुजर रहा है।

### नेशनल हाईवे या 'सूरजपुर जलमार्ग'?-

शहर के नेशनल हाईवे की तस्वीरें व्यवस्था की कहानी खुद बयान कर रही हैं, सड़क पर इतना पानी जमा है कि दोपहिया वाहन चालक संभलकर निकलने को मजबूर हैं, भारी वाहनों के गुजरने पर सड़क पर जमा पानी चारों तरफ फैलता है, विडंबना यह है कि जिस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, उसी मार्ग पर जलभराव लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, व्यंग्य में कहें तो सूरजपुर में बारिश के मौसम में नेशनल हाईवे का एक नया विभागीय उन्नयन हो जाता है–'नेशनल हाईवे से नेशनल वाटरवे', बस अंतर इतना है कि इस जलमार्ग पर नाव नहीं चलती, बल्कि बाइक, कार और ट्रक अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार तैरते हुए नजर आते हैं।

**पुराना अस्पताल बना 'मानसून तालाब'**–शहर का पुराना अस्पताल क्षेत्र भी बारिश में जलभराव की समस्या से अछूता नहीं है, अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान के आसपास पानी का जमा होना अपने आप में गंभीर सवाल है,अस्पताल वह जगह है जहां स्वस्थ व्यक्ति नहीं,बल्कि इलाज और मदद की जरूरत वाले लोग पहुंचते हैं,ऐसे में यदि वहां पहुंचने के रास्ते में ही पानी जमा हो जाए तो व्यवस्था की प्राथमिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, शहर में तालाबों की कमी हो तो पुराना अस्पताल परिसर काम आ सकता है– कम से कम बारिश के मौसम में तस्वीर तो यही बता रही है।

**कचरा नाली में...पानी सड़क पर और जिम्मेदारी हवा में**–जलभराव की समस्या को केवल बारिश के माथे मढ़ देना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि बारिश का पानी आखिर निकलेगा कहां? यदि नालियां साफ हों, जल निकासी के मार्ग खुले हों और पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा न हो तो सामान्य बारिश के बाद सड़कों पर लंबे समय तक पानी जमा रहने की स्थिति नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहां तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। नालियों में कचरा जमा है, पानी के रास्ते अवरुद्ध हैं और बारिश होते ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, फिर शुरू होता है वही पुराना खेल–जनता शिकायत करती है, अधिकारी निरीक्षण करते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं और पानी अपने आप उतर जाता है, अगली बारिश तक समस्या फिर जस की तस।

**चुनाव खत्म,अब जनता किस दरवाजे पर जाए?**- नगरीय निकाय चुनाव अभी हुए हैं, चुनाव के दौरान शहर की समस्याएं, विकास और नागरिक सुविधाएं हमेशा चर्चा के केंद्र में रहती हैं, जनता भी उम्मीद करती है कि चुनाव के बाद सड़क,नाली,सफाई और जल निकासी जैसी मूलभूत समस्याओं पर तेजी से काम होगा, लेकिन बारिश ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है,सूरजपुर नगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता है,क्षेत्रीय विधायक भाजपा के हैं और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने से ज्यादा जरूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करना है,जनता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कांग्रेस की सीमा से आया है या भाजपा की सीमा से, जनता को बस पानी सड़क से हटता हुआ चाहिए,लेकिन स्थिति देखकर लगता है कि जिम्मेदारी भी शायद उसी पानी की तरह है–एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर बहती रहती है।

**'वोट लो और फिर मजे करो' वाली व्यवस्था?**- शहर के लोगों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि चुनाव के समय जिस जनता की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है, चुनाव के बाद वही समस्या प्राथमिकता सूची में नीचे क्यों चली जाती है? सड़क पर पानी भरा हो,नालियां जाम हों,कचरा जमा हो और लोगों को आवागमन में परेशानी हो–तो यह केवल बारिश की समस्या नहीं है। यह नगर प्रबंधन की तैयारी और नियमित निगरानी का भी सवाल है, अगर हर साल बारिश के बाद यही स्थिति बनती है तो फिर हर साल बारिश को दोष देना कुछ वैसा ही है जैसे परीक्षा में फेल होने के बाद किताब को दोष देना, बारिश तो अपना काम करेगी ही, सवाल यह है कि नगर व्यवस्था अपना काम कब करेगी?

**सूरजपुर में विकास की असली परीक्षा बारिश ले रही है**- किसी शहर के विकास का आकलन बड़े भवनों, रंग-रोगन,स्ट्रीट लाइट और सजावटी कार्यों से ही नहीं होता,असली परीक्षा तब होती है जब तेज बारिश होती है, बारिश के दौरान पानी कितनी जल्दी निकलता है? नालियां कितनी साफ हैं? मुख्य सड़कों पर जलभराव कितना होता है? आम नागरिक कितनी आसानी से आवागमन कर सकता है? इन सवालों के जवाब ही शहर की वास्तविक व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, और फिलहाल सूरजपुर की तस्वीरें इस रिपोर्ट कार्ड पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं।

**सफाई और नाली व्यवस्था की हो नियमित निगरानी**- शहर में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए केवल बारिश के समय पंप लगाने या पानी निकालने से काम नहीं चलेगा,नालियों की नियमित सफाई, अवैध अवरोधों को हटाना,कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई,जल निकासी के प्रमुख बिंदुओं की पहचान और बारिश से पहले व्यापक सफाई जरूरी है,साथ ही यह भी देखना होगा कि जिन नालियों का निर्माण हुआ है,उनका पानी वास्तव में कहां जा रहा है और क्या उनकी क्षमता शहर की मौजूदा आबादी एवं निर्माण के अनुरूप है, क्योंकि यदि नाली में पानी नहीं जा रहा और सड़क पर पानी ही पानी है,तो फिर सवाल केवल बारिश का नहीं–योजना, निर्माण, सफाई और निगरानी चारों का है।

**अब तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं...**- सूरजपुर की बारिश ने कोई नई समस्या पैदा नहीं की है। उसने सिर्फ पुरानी समस्या को कैमरे के सामने ला दिया है,सड़क पर जमा पानी,बंद नालियां,कचरे से भरे निकासी मार्ग और जलमग्न सार्वजनिक स्थल शहर की उस व्यवस्था का आईना हैं,जिसकी चर्चा चुनावों में विकास के नाम पर होती है,अब जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी इन तस्वीरों को केवल सोशल मीडिया की तस्वीर न मानें, बल्कि व्यवस्था की जांच रिपोर्ट मानकर देखें, क्योंकि जनता को हर मानसून में यह तय करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह सड़क से जा रही है, नाले से या नदी से, सूरजपुर को शहर ही रहने दीजिए साहब...हर बारिश में उसे तालाब और नदी बनाने की जरूरत नहीं है।

# ई-ऑफिस में स्वास्थ्य विभाग का जलवा...जुलाई में नस्तियों के निस्तारण में मिला पहला स्थान

## छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया प्रशंसा-पत्र...स्वास्थ्य मंत्री ने सचिव अमित कटारिया समेत पूरी टीम को दी बधाई...

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी कामकाज में फाइलों की रफ्तार अक्सर चर्चाओं में रहती है, किसी फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा,यह सवाल आमतौर पर व्यवस्था की कार्यप्रणाली से जुड़ा माना जाता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए नस्तियों के निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जुलाई 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर से 31 अगस्त 2026 को जारी प्रशंसा-पत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जुलाई 2026 की अवधि में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों के निस्तारण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया है,प्रशंसा-पत्र पर मुख्य सचिव विकास शील के हस्ताक्षर हैं, शासन की ओर से जारी इस प्रमाण-पत्र को विभाग के लिए प्रशासनिक कार्यप्रणाली और डिजिटल फाइल निस्तारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

### फाइलें अब टेबल पर नहीं, ई-ऑफिस में दौड़ रहीं...

सरकारी दफ्तरों में फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने की शिकायतें कोई नई बात नहीं हैं, कई बार एक फाइल के आगे बढ़ने के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, ऐसे में ई-ऑफिस व्यवस्था को सरकारी कामकाज में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जुलाई 2026 के दौरान इसी डिजिटल प्रणाली के जरिए नस्तियों के निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन किया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रशंसा-पत्र में विभाग को अन्य विभागों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर प्रथम स्थान दिए जाने की पुष्टि की गई है, यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का काम सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है, अस्पताल, चिकित्सकीय सेवाएं, दवाइयां, स्वास्थ्य योजनाएं, मानव संसाधन और विभागीय प्रशासन से जुड़े अनेक निर्णय लगातार प्रक्रिया में रहते हैं, ऐसे में फाइलों का समय पर निस्तारण प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

### स्वास्थ्य मंत्री ने दी पूरी टीम को बधाई...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी, उन्होंने ई-ऑफिस के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की,मंत्री ने अपने संदेश में विभागीय टीम को इसी तरह निष्ठा और समर्पण के साथ उत्कृष्ट कार्य करते हुए स्वास्थ्य विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की शुभकामनाएं दीं।

### डिजिटल व्यवस्था से बढ़ सकती है जवाबदेही...

ई-ऑफिस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि फाइलों की आवाजाही डिजिटल माध्यम से दर्ज होती है, इससे यह पता लगाना अपेक्षाकृत आसान होता है कि कोई नस्ती किस स्तर पर है और उसके निस्तारण में कितना समय लगा, स्वास्थ्य विभाग का जुलाई में प्रथम स्थान प्राप्त करना यह संकेत देता है कि डिजिटल फाइल प्रणाली के इस्तेमाल में विभाग ने प्रभावी प्रदर्शन किया है, हालांकि वास्तविक प्रशासनिक सुधार का आकलन केवल निस्तारित नस्तियों की संख्या से नहीं,बल्कि निर्णयों की गुणवत्ता,समयबद्धता और आम लोगों को मिलने वाले परिणामों से भी होना चाहिए,यानी ई-ऑफिस में फाइल तेज दौड़े, यह अच्छी बात है,लेकिन उस फाइल से निकला आदेश जमीन पर कितनी तेजी से पहुंचता है,असली परीक्षा वहां होगी।

शासन की ओर से प्रथम स्थान का प्रशंसा-पत्र मिलने के बाद विभाग के सामने इस प्रदर्शन को लगातार बनाए रखने की चुनौती भी होगी, जुलाई में हासिल उपलब्धि को केवल एक महीने की सफलता तक सीमित रखने के बजाय यदि विभाग इसे नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाता है, तो इसका सीधा लाभ प्रशासनिक दक्षता को मिल सकता है, खासकर स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग में लंबित नस्तियों का समय पर निस्तारण कई प्रशासनिक निर्णयों को गति दे सकता है, यही वजह है कि ई-ऑफिस में मिली यह उपलब्धि महज एक रैंकिंग नहीं, बल्कि विभागीय कामकाज को डिजिटल और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है, अब देखना होगा कि जुलाई की यह 'प्रथम रैंक' आगे भी बरकरार रहती है या फिर दूसरे विभाग ई-ऑफिस की इस दौड़ में स्वास्थ्य विभाग को पीछे छोड़ने के लिए अपनी फाइलों को और तेज दौड़ाते हैं।

CMYK

# कौन हैं नीतीश राजपूत? 2.5 करोड़ की मानहानि झेलने वाले यूट्यूबर

रिसर्च बेस्ड आधारित वीडियो के लिए मशहूर यूट्यूबर नीतीश राजपूत बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं। हाल ही में एसएससी परीक्षा विवाद और मानहानि केस से चर्चा में आए नीतीश की इस नई एंट्री से फैंस में भारी उत्सुकता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में अपने रिसर्च बेस्ड वीडियो और देश विदेश के मुद्दों पर सटीक विश्लेषण के लिए मशहूर नीतीश राजपूत जल्द ही छोटे पर्दे के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं। इस बात को लेकर मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। देश के जटिल राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विषयों पर गहराई से बात करने वाले किसी यूट्यूबर का ऐसे ड्रामा और मनोरंजन से भरे मंच पर आना फैंस के लिए बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बता दें, बिग बॉस 20 6 सितंबर से प्रसारित होने वाला है।

**कौन हैं नीतीश राजपूत?**

नीतीश राजपूत ने डिजिटल स्पेस में अपनी एक अनूठी और मजबूत पहचान बनाई है। वे अक्सर देश के ज्वलंत मुद्दों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत शोध के साथ वीडियो बनाते हैं। उनका प्रस्तुत करने का तरीका और तथ्यों पर आधारित बातें दर्शकों को काफी पसंद आती हैं। यही वजह है कि उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब उनके प्रशंसक यह देखने के लिए बेताब हैं कि जो इंसान स्क्रीन पर केवल गंभीर विषयों पर तथ्यों के साथ बात करता है, वह बिग बॉस के घर के भीतर बनने वाले दबाव, बहसबाजी और रणनीतिक माहौल में खुद को कैसे ढालता है। बता दें, बीते साल 2025 में नीतीश ने दावा किया था कि उन्हें और उनके यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है और उसकी वजह बलूचिस्तान पर बनाया गया एक वीडियो है।

**हालिया विवादों और कानूनी पचड़ों के कारण रहे सुर्खियों में**

नीतीश राजपूत का नाम हाल ही में एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे और कानूनी विवाद को लेकर भी खबरों में रहा था। उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की प्रणाली पर एक विस्तृत वीडियो बनाया था। इस वीडियो ने लाखों अभ्यर्थियों का ध्यान खींचा और देश भर में एक नई बहस छेड़ दी। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला काफी बढ़ गया और परीक्षा आयोजित कराने वाली एक प्रमुख एडुकुइटी टेक्नोलॉजीज ने उन पर ढाई करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया। इस कानूनी चुनौती के बावजूद नीतीश अपने बयान और शोध पर पूरी तरह कायम रहे। उनका कहना था कि उनकी पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित थी। इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और आम जनता के बीच और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया।

**बिग बॉस 20 के घर में किन दिग्गजों के साथ हो सकता है सामना?**

यदि नीतीश राजपूत इस शो का हिस्सा बनते हैं तो उनका सामना मनोरंजन, स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया जगत के कई अन्य चर्चित चेहरों से होने की संभावना है। इस सीजन के संभावित प्रतियोगियों में कुशल तंवर (गुल्लू), भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे,टीवी अभिनेत्री कनिका मान,खुशी दुबे,रैपर शैंटी शर्मा,मॉडल ईशा रिखी,सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरिशफा खान,मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम,अभिनेता अमन गांधी,गायक काजी तौकीर,पूर्व अभिनेत्री गीता बसरा और शोविक चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि शो की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही प्रतियोगियों के अंतिम नामों पर मुहर लगेगी।

**सलमान खान की मेजबानी और शो के प्रीमियर का समय**

बिग बॉस के इस मील के पत्थर यानी 20वें सीजन को एक बार फिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ही होस्ट करने जा रहे हैं। शो के प्रोमो ने दर्शकों के बीच नए ट्विस्ट और रहस्य को लेकर पहले ही जबरदस्त माहौल बना दिया है। बिग बॉस 20 का पहला ग्रैंड एपिसोड 6 सितंबर 2026 को ऑन-एयर होगा। इसे रात 9 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर और उसके बाद रात 10: 30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा।

# हे बेबी 2 का हुआ ऐलान,19 साल बाद लौटेगी अक्षय कुमार की हिट कॉमेडी,क्या लौटेगी पुरानी स्टारकास्ट?

साजिद नाडियाडवाला ने 'हे बेबी' की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी। हालांकि अक्षय कुमार, विद्या बालन,रितेश देशमुख और फर्दीन खान की वापसी पर अभी फैसला नहीं हुआ है। बॉलीवुड की चर्चित कॉमेडी फिल्मों में शामिल 'हे बेबी' एक बार फिर दर्शकों के बीच वापसी करने जा रही है। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म का अब सीक्वल बनने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने 'हे बेबी' को लेकर बड़ा ऐलान किया है। खास बात यह है कि सीक्वल की शूटिंग एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी, जहां फिल्म के पहले भाग के कई अहम हिस्से फिल्माए गए थे।

**ऑस्ट्रेलिया में शूट होगी 'हे बेबी'**

साजिद नाडियाडवाला ने गुरुवार को न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स का मुंबई स्थित अपने ऑफिस में स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी आने वाली तीन फिल्मों की शूटिंग को लेकर एक समझौते की घोषणा की। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में 'हे बेबी' भी शामिल है। यह साझेदारी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग का हिस्सा है,जिसे सिडनी स्थित टेम्पल के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समझौते के तहत प्रोडक्शन हाउस अपनी तीन आगामी फिल्मों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में करेगा।

**पहली फिल्म से जुड़ी यादें भी कीं साझा**

साजिद नाडियाडवाला ने ऑस्ट्रेलिया में दोबारा शूटिंग करने को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती के साथ-साथ वहां का फिल्म निर्माण माहौल भी काफी बेहतर है। उनके मुताबिक वहां काम करने वाले पेशेवरों का रवैया सहयोगी और व्यवस्थित रहा है, जिसके कारण उनकी टीम का पिछला अनुभव बेहद यादगार रहा। नाडियाडवाला ने यह भी बताया कि निर्देशक से लेकर पूरी प्रोडक्शन टीम तक ने ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग के दौरान शानदार समय बिताया था। ऐसे में अब तीन नई फिल्मों के साथ दोबारा वहां जाना उनके लिए खास अनुभव होगा।

**प्रीमियर क्रिस मिन्स ने भी जताई खुशी**

न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग करने के फैसले को राज्य के फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का ऑस्ट्रेलिया को अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए चुनना वहां के स्क्रीन उद्योग में भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने यह भी याद किया कि नाडियाडवाला की टीम करीब दो दशक पहले 'हे बेबी' की शूटिंग के लिए न्यू साउथ वेल्स आई थी। अब उसी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए टीम का वापस लौटना दोनों पक्षों के पुराने संबंधों को भी मजबूत करता है।

**क्या पुरानी स्टारकास्ट की होगी वापसी?**

2007 में रिलीज हुई 'हे बेबी' में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख,फर्दीन खान और विद्या बालन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी तीन ऐसे कुंवारे दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती थी, जिनकी जिंदगी अचानक एक बच्चे के आने से पूरी तरह बदल जाती है। कॉमेडी,भावनाओं और रिश्तों के मिश्रण वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी,हालांकि समीक्षकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। पहली फिल्म का निर्देशन साजिद खान ने किया था और निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीक्वल में पुरानी स्टारकास्ट में से कौन-कौन कलाकार वापस आएगा और क्या साजिद खान ही फिल्म का निर्देशन करेंगे।

**फिल्म की कहानी को लेकर भी रहेगी दिलचस्पी**

'हे बेबी' की कहानी को लेकर पहले भी चर्चा रही है,क्योंकि इसकी मूल कहानी का मेल मलयालम फिल्म 'थूवलस्पर्शम',हॉलीवुड फिल्म 'थ्री मेंस एंड ए बेबी ' और फ्रेंच फिल्म 'थ्री मेन एंड ए क्रेडेल ' से जोड़ा गया था। अब सीक्वल की घोषणा के बाद दर्शकों की नजर इस बात पर होगी कि नई फिल्म पिछली कहानी को आगे बढ़ाती है या पूरी तरह नए अंदाज में तीन किरदारों और बच्चे की कहानी पेश करती है। फिलहाल 'हे बेबी' की रिलीज डेट, कलाकारों और निर्देशक को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग की पुष्टि ने इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल को लेकर दर्शकों की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है।

# शाहरुख खान की फिल्म के लिए कई सितारों ने दिया था ऑडिशन

बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज के समय भले ही बड़ी कमाई न कर पाई हों, लेकिन बाद में उन्हें क्लासिक फिल्मों का दर्जा मिल गया। ऐसी ही एक फिल्म है शाहरुख खान की स्वदेश, जिसे आज उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। साल 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से काफी सराहना मिली। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग भी 8.2 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे? मेकर्स की पहली पसंद आमिर खान थे। आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी स्वदेश में शाहरुख खान ने मोहन भार्गव नाम के एक नासा वैज्ञानिक का किरदार निभाया था, जो भारत लौटकर गांव के लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। फिल्म में देश,समाज और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाया गया था।

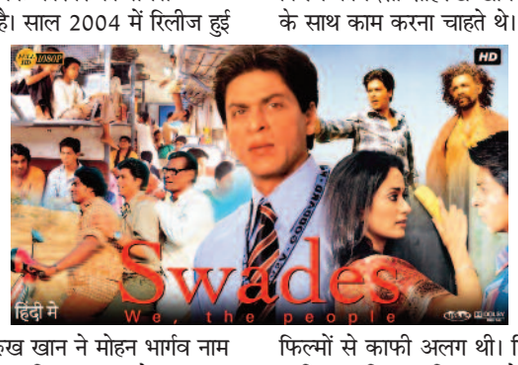


**आमिर खान को ऑफर हुई थी फिल्म**

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वदेश के लिए सबसे पहले आमिर खान से संपर्क किया गया था। फिल्म के लेखक अमीन हाजी ने बताया था कि आमिर खान को कहानी पसंद आई थी और वह फिल्म में अभिनय के साथ-साथ प्रोडक्शन से भी जुड़ने के इच्छुक थे। आमिर खान उस समय कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, जिसकी वजह से फिल्म की तारीखों को लेकर समस्या सामने आई। मेकर्स फिल्म को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करवाना चाहते थे और इसके बाद शाहरुख खान को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। शाहरुख खान की एंट्री ने बदली फिल्म की दिशा शाहरुख खान उस समय आशुतोष गोवारिकर के साथ काम करना चाहते थे। लगान देखने के बाद शाहरुख खान निर्देशक से प्रभावित हुए थे। आमिर खान की व्यस्तता और शाहरुख की दिलचस्पी के कारण आखिरकार यह फिल्म शाहरुख खान के पास पहुंची। शाहरुख ने मोहन भार्गव के किरदार में एक अलग ही अंदाज दिखाया। यह उनकी सामान्य रोमांटिक फिल्मों से काफी अलग थी। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो विदेश में सफल करियर बनाने के बाद अपनी जड़ों की ओर लौटता है।

**आर माधवन ने भी दिया था ऑडिशन**

स्वदेश से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा यह है कि अभिनेता आर माधवन ने भी इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। इसके अलावा ऋतिक रोशन को भी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी। हालांकि,अंतिम रूप से मोहन भार्गव का किरदार शाहरुख खान को मिला। आर माधवन उस दौर में अपनी अलग पहचान बना रहे थे और कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में थे। लेकिन फिल्म की कहानी और किरदार के लिए शाहरुख खान को चुना गया।

# सिद्धार्थ तमन्ना के किसिंग वीडियो ने मचाई हलचल जानें क्या है हकीकत

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से जुड़े कलाकारों के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते रहते हैं। हाल ही में अभिनेत्री कियारा आडवाणी और अभिनेता यश की फिल्म टॉक्सिक के कुछ सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई। इसी बीच एक वीडियो वायरल होने लगा,जिसमें दावा किया गया कि कियारा के यश के साथ इंटीमेट सीन के बाद उनके पति और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ किसिंग सीन दिया है। हालांकि जांच में सामने आया कि यह दावा सही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया का किसिंग वीडियो असली नहीं बल्कि एआई से बनाया गया फर्जी वीडियो है। वीडियो में एआई जनरेशन से जुड़े संकेत भी दिखाई दिए, जिसके बाद इसकी वास्तविकता पर सवाल उठे। दरअसल,यश और कियारा आडवाणी की फिल्म टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स रिलीज से पहले ही चर्चा में थी। फिल्म के कुछ रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी। कई लोगों ने इन सीन्स पर प्रतिक्रिया दी, जबकि कुछ लोगों ने कलाकारों का समर्थन भी किया।

## खेल समाचार

# एशियन गेम्स के लिए भारत-पाकिस्तान समेत 7 टीमों का हो चुका है ऐलान

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** एशियन गेम्स 2026 का 19 सितंबर से आगाज होगा, जिसमें क्रिकेट का जलवा भी देखने को मिलेगा। मेन्स और वूमेन्स दोनों कैटेगिरी में टीमें गोल्ड मेडल के लिए एक-दूसरे से भिड़ती नजर आएंगी। मेन्स कैटेगिरी में मेजबान जापान समेत कुल 10 टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें 5 टीमें आईसीसी फुल मेंबर नेशन हैं। ऐसे में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। मेन्स क्रिकेट का आयोजन 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। जैसे-जैसे टूर्नामेंट की तारीख नजदीक आ रही है,टीमों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। अब तक 7 टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। 3 टीमों ने अब तक अपने स्क्वाड से पर्दा नहीं उठाया है। एशियन गेम्स 2026 के लिए अब तक किन-किन टीमों ने किया है अपने स्क्वाड का ऐलान...

**एशियन गेम्स 2026 के लिए सभी मेन्स टीमों का स्क्वाड**

**अफगानिस्तान:** दरविश रसूली (कप्तान), अब्दुल्ला अहमदजई,मोहम्मद अकरम,इस्मत आलम,फरीदून दाऊदजई,हसन ईसाखिल, मोहम्मद इशाक,करीम जनत,फैसल खान, नांग्याल खरोती,इमरान मीर,अरब गुल मोमंद, फरमानुल्लाह सफी,खालिद तानिवाल, नजीबुल्लाह जादरान।

**बांग्लादेश:** लिटन दास (कप्तान),तंजीद हसन,परवेज हुसैन इमोन,मोहम्मद सैफ हसन,नजमुल हुसैन शान्तो,तौहीद हृदोय, मुसद्देक हुसैन सैकत,यासिर अली चौधरी, रिशाद हुसैन,शाक महेदी हसन,नसुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद

**हांगकांग:** टीम का ऐलान होना अभी बाकी है।

**भारत:** श्रेयस अय्यर (कप्तान),अभिषेक शर्मा,संजू सैमसन,इशान किशन,शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी,अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर,वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई,जसप्रीत बुमराह,हर्षित राणा,अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी

**जापान:** केंडेल कादोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान),चार्ली हारा-हिंज, बेंजामिन इतो-डेविस, एलेस्टर कादोवाकी-फ्लेमिंग,कोहेई कुबोटा,जेक कुसुदा-नायरन,वतरू मियाउची, रेओ सकुरानो-थॉमस,एलेक्स शिराई-पटमोर,शोमा सुगाया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी, त्सुयोशी तकादा, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लाचलान यामामोटो-लेक

**मलेशिया:** टीम का ऐलान होना अभी बाकी है

**नेपाल:** दीपेंद्र सिंह ऐरी (कप्तान),रोहित कुमार पौडेल,सोमपाल कामी,करण केसी, संदीप लामिछाने,आरिफ शेख,आसिफ शेख, कुशल भुर्टेल,ललित राजबंशी,गुलसन कुमार झा,नंदन यादव,लोकेश बम, सुदीप जोरा,शेर मल्ला, कुशल मल्ला।

**ओमान:** सुफयान महमूद (कप्तान), मुजफ्फर शिरलकर, मोहम्मद अली अल बलुशी,जुबैर अल बलुशी,शुएब अल बलुशी,नावेद अल बलुशी, वसीम अल बलुशी,अहमद अल जदजाली,समीर ओथमान, वहीद अल बलुशी, फारिस अल बलुशी, मोहम्मद उस्मान, इस्सा रहीम अल बलुशी, अब्दुल जलील, कैस अल बलुशी।

**पाकिस्तान:** साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान),अबरार अहमद, अहमद दानियाल,आकिफ जावेद,अली रजा, अराफात मिन्हास,हैदर अली,हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम, उस्मान खान।

**श्रीलंका:** टीम का ऐलान होना अभी बाकी है।

# वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और मौका

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** वैभव सूर्यवंशी को एक और मौका मिलने जा रहा है,जो काफी अहम है। वे इस वक्त दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं,जिसमें वो जिस टीम से खेल रहे है,वो ईस्ट जोन फाइनल में पहुंच चुकी है। अब तक उन्होंने दलीप ट्रॉफी के इस सीजन दो मैच खेले हैं और केवल एक ही हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से आई है। वैसे भी अभी तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वैभव उस तरह का कमाल नहीं दिखा पाए हैं, जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही है। अब वे रविवार को फिर से खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे।

**ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच होगा दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच**

दलीप ट्रॉफी के फाइनल की दो टीमें पक्की हो चुकी हैं। ईस्ट जोन की कमान ईशान किशन के पास है, वहीं साउथ जोन की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच खिताब के लिए फाइनल में आमना सामना होगा। मैच 6 सितंबर यानी रविवार से शुरू होगा, जो कि चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ईस्ट जोन से ही वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं।

**दो मैच,तीन पारियां और केवल एक ही अर्धशतक**

वैभव जब नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उतरे तो वे पहली पारी में केवल आठ रन बनाकर आउट हो गए। मैच की दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई। इसके बाद जब सेमीफाइनल में वे सेंट्रल जोन के खिलाफ उतरे तो पहली पारी में जरूर उन्होंने 92 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में केवल 40 रन बनाकर आउट हो गए। यानी दो मैचों की तीन पारियों में केवल एक अर्धशतक उनके नाम पर है।

**अब तक ऐसा रहा है वैभव का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रिकॉर्ड**

टी20 क्रिकेट में अपने बैट से धमाका करने वाले वैभव का प्रथम श्रेणी में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। वे 10 मैचों की 15 पारियों में केवल 347 रन ही बना सके हैं। इसमें दो अर्धशतक उनके नाम हैं। यहां उनका औसत 23.13 का, जिसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अब उनके पास मौका होगा कि ईस्ट जोन को ना केवल खिताब जिताएं, बल्कि खुद भी बड़ी पारी खेलें। अब वे पहले ही दिन बैटिंग के लिए आएंगे या फिर इंतजार करना पड़ेगा, ये तो रविवार को ही पता चलेगा।

# ऑस्ट्रेलिया के लिए 2027 वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी में निखिल चौधरी

**नई दिल्ली,03 सितम्बर 2026।** भारत में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर निखिल चौधरी की नज़रें आने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर हैं, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वनडे डेब्यू करना चाहते हैं। दिल्ली के रहने वाले चौधरी पिछले छह दशकों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में जन्मे पहले पुरुष क्रिकेटर हैं;उन्होंने जून में बांग्लादेश के खिलाफ अपना टी20 आई डेब्यू किया था। यह स्पिन ऑलराउंडर जल्द ही इंडिया ए के खिलाफ अनऑफिशियल वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे और भविष्य में ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में जगह बनाने और 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर उनकी नज़र है। चौधरी ने कहा, मैं 50 ओवर का क्रिकेट खेलना चाहता हूं और अगर मौका मिला तो टेस्ट भी खेलना चाहता हूं। मेरा पहला लक्ष्य 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है और उसके बाद अगले साल होने वाला टी 20 वर्ल्ड कप। मैं जब तक हो सके ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं।

# तौहीद हृदोय ने रचा इतिहास 350 रन की पारी से तोड़ा तमीम का रिकॉर्ड

**ढाका,03 सितम्बर 2026।** बांग्लादेश के युवा बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। शानदार बल्लेबाजी करते हुए हृदोय ने 350 रनों की मैराथन पारी खेलकर तमीम इकबाल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने घरेलू क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हृदोय की बल्लेबाजी में धैर्य, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने लंबे समय तक क्रीज पर टिककर गेंदबाजों को परेशान किया और टीम के स्कोर को विशाल स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तौहीद हृदोय ने अपनी पारी के दौरान शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और बाद में तेजी से रन बनाते हुए दोहरा शतक पार किया। इसके बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 350 रन का आंकड़ा छू लिया। उनकी इस पारी में कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले। हृदोय ने मैदान के चारों ओर रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा।

**तमीम इकबाल का रिकॉर्ड टूटा**

इस शानदार पारी के साथ हृदोय ने बांग्लादेश क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज तमीम इकबाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तमीम इकबाल लंबे समय से बांग्लादेशी क्रिकेट में बड़ी पारियों के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन हृदोय की 350 रन की पारी ने एक नया इतिहास लिख दिया। यह प्रदर्शन बांग्लादेश क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं के उभरने का संकेत भी माना जा रहा है।

**धैर्य और आक्रामकता का शानदार मेल**

हृदोय की पारी की सबसे बड़ी खासियत उनका संयम रहा। लंबे प्रारूप में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने विकेट बचाने के साथ-साथ रन गति को भी बनाए रखा। शुरुआती चरण में उन्होंने गेंदबाजों को सम्मान दिया, लेकिन सेट होने के बाद बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। उनकी बल्लेबाजी में क्लासिक तकनीक और आधुनिक क्रिकेट का आक्रामक अंदाज दोनों देखने को मिला। मुकाबले में हृदोय ने उस समय जिम्मेदारी संभाली जब टीम को एक बड़ी पारी की जरूरत थी। उन्होंने साझेदारियां बनाईं और विरोधी टीम को वापसी का मौका नहीं दिया। उनकी पारी की बदौलत टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

**क्रिकेट जगत में हो रही तारीफ**

हृदोय की इस ऐतिहासिक पारी के बाद क्रिकेट जगत में उनकी जमकर प्रशंसा हो रही है। पूर्व खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने उनकी बल्लेबाजी को शानदार बताया है।

**नाम परिवर्तन सूचना**

मैं समिउद्दीन (माता/पिता/पालक का नाम) पिता निजामुद्दीन,उम्र लगभग 42 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम सोनपुर (शि.) पोस्ट बंजा,पुलिस चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर, तहसील भैयाथान,जिला-सूरजपुर (छ.ग.) का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपनी नाबालिग पुत्री का नाम गुलजरा GULJARA जन्मतिथि 01/01/2012 से बदलकर अपनी पुत्री का नाम शायरा परवीन SHAYARA PARVIN जन्मतिथि 05/10/2010 करवाना चाहता हूँ। मैं अपनी पुत्री का नाम बदलकर यदि कोई भी गैर कानूनी काम करता हूँ तो उसके लिये मैं स्यं जिम्मेदार रहूँगा। मेरी पत्नी शहजीदन बीबी (पत्नी का नाम) को हमारे नाबालिग पुत्री का नाम एवं जन्मतिथि बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह शपथपत्र अपने पूरे होशो हवास में रहकर हस्ताक्षर कर रहा हूँ तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
**समिउद्दीन**

# खंडन नहीं, जवाब चाहिए! 50 खबरों के बाद भी क्यों अनुत्तरित हैं सवाल?




# 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति पर विभाग से सीधे सवाल!

**जिस प्रतिष्ठित अखबार के लिए खंडन छापने का दबाव बनाया.जा रहा था, उसे दैनिक घटती घटना के सवालों का जवाब देना चाहिए!**


कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़
ब्लॉक-1, पुरानी बस्त, दल्यवती पवन, नया रायपुर, पिन कोड-492002.
दूरभाष क्र. 0771-2235226, ई-मेल आई.डी. controllerraipur@gmail.com

क्रमांक/स्था./2026/1747 नवा रायपुर, दिनांक 20/08/2026

प्रति :
सम्पादक
दैनिक समाचार पत्र – [redacted]
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय – दैनिक समाचार पत्र "[redacted]" में प्रकाशित समाचार – "प्रमोशन पॉलिसी पर उठे गंभीर सवाल – 12वी पास 13 सहायकों को बना दिया फूड सेफ्टी ऑफिसर" का खांडन।

—•—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 20.08.2026 को दैनिक समाचार पत्र पत्रिका में समाचार – "प्रमोशन पॉलिसी पर उठे गंभीर सवाल – 12वीं पास 13 सहायकों को बना दिया फूड सेफ्टी ऑफिसर" प्रकाशित किया गया है। यह पुर्णतः असत्य, अमह एवं तथ्यों के मनगढंत बिना विना प्रकाशित किया गया समाचार है। इस विषय में खाद्य एवं औषधि, छत्तीसगढ़ की ओर से विभागीय एवं वैधानिक तथ्यों के साथ खांडन निम्नवुसार है –

**विज्ञप्ति जारी**

### दैनिक घटती घटना ने उठाए ये सवाल

- डिंग्री थी तो नमूना सहायक क्यों बने?
- 10% से 25% पदोन्नति कोटा 3 महीने पहले ही क्यों बढ़ा दिया गया?
- सीधी भर्ती से पहले पदोन्नति क्यों?
- डीपीसी ने किन आधारों पर की जांच?
- क्या विभागीय परीक्षा हुई या सिर्फ कागजी जांच?
- हस्ताक्षर किसके? प्राधिकरण आदेश कहां है?
- डीपीसी के विवादित सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल?

### पदोन्नत 13 नमूना सहायकों की सूची (विभागीय विज्ञप्ति के अनुसार)

| क्र. | नाम | शैक्षणिक योग्यता | क्र. | नाम | शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कु. अंजली नायक | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) | 8 | सुश्री निधि यादव | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) |
| 2 | कु. सुमन अग्रवाल | एम.एस.सी. (बायोटेक्नोलॉजी) | 9 | श्री दुलेश्वर सिंह | एम.एस.सी. (माइंक्रोबायोलॉजी) |
| 3 | निधि जारसवाल | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) | 10 | श्री प्रमोद कुमार पैकरा | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) |
| 4 | सुमन ठाकुर | एम.एस.सी. (बायोटेक्नोलॉजी) | 11 | श्री कृष्ण प्रताप सिंह | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) |
| 5 | सुश्री दीपा साहू | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) | 12 | सुश्री ऋषित मरावी | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) |
| 6 | सुश्री दिव्या सिंह राजपूत | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) | 13 | सुश्री ऋतमणी कंवर | बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) |
| 7 | डॉ. अर्चना तिवारी | एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र) | | | |

नोट : विभाग के अनुसार इन सभी की शैक्षणिक योग्यता, सेवा अवधि एवं दस्तावेजों की जांच के बाद डीपीसी ने पदोन्नति की अनुशंसा की।

**लगभग 50 खबरों के बाद भी विभाग मौन क्यों?**

**नियम, राजपत्र संशोधन, नियुक्ति आदेश, डीपीसी की कार्यवाही और प्राधिकरण आदेश सार्वजनिक करे विभाग तभी खत्म होगा विवाद!**

# पहले नमूना सहायक, अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी...डिग्री तब भी थी साहब!

## 13 डिग्रीधारियों का 'नमूना' से 'सुरक्षा अधिकारी' तक सफर, बीच में बदला प्रमोशन का गणित

**13 नमूना सहायकों का प्रमोशन मामले में खंडन आया,लेकिन सवाल और बढ़ गए,डिग्री पहले से थी तो एफएसओ की सीधी भर्ती क्यों नहीं? 25% कोटा बढ़ाने की टाइमिंग भी घेरे में...**

**'12 वीं पास' खबर के खंडन में 13 डिग्रीधारी सामने आए,अब विभाग से बड़ा सवाल...पहले नमूना सहायक क्यों?**

**10 से 25% हुआ प्रमोशन कोटा,फिर 13 नमूना सहायकों की राह हुई आसान? नियम संशोधन की टाइमिंग से लेकर डीपीसी की भूमिका तक कई सवाल अनुत्तरित**

**प्रमोशन नियमसम्मत तो पूरी फाइल सार्वजनिक करने में हिचक क्यों? 13 नमूना सहायकों की योग्यता,25% कोटा और डीपीसी की कार्यवाही पर पारदर्शिता की मांग**

-न्यूज डेस्क-

**रायपुर,03 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।** खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए जाने का मामला अब एक खबर और उसके खंडन के बीच का विवाद भर नहीं रह गया है,विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति ने भले ही एक प्रतिष्ठित अख़बार के एक प्रकाशित खबर को 'असत्य, निराधार एवं काल्पनिक'बताया हो,लेकिन जिस तरह खंडन में कुछ बिंदुओं का जवाब दिया गया और कई मूल सवालों पर चुप्पी बनी रही,उससे विवाद और गहरा गया है। 20 अगस्त 2026 को नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,छत्तीसगढ़ की ओर से जारी चार पेज की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता,सेवा अवधि और दस्तावेजों की जांच के बाद की गई है,विज्ञप्ति में 13 पदोन्नत कर्मचारियों के नाम और उनकी शैक्षणिक योग्यताएं भी दर्ज हैं,विभाग का यह स्पष्टीकरण निश्चित रूप से रिकॉर्ड का हिस्सा है,लेकिन क्या इससे पूरा विवाद समाप्त हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं है कि इन 13 कर्मचारियों के पास कौन-कौन सी डिग्री हैं,असली सवाल यह है कि इन डिग्रियों और उनकी मूल नियुक्ति,पदोन्नति के नियम,25 प्रतिशत कोटा तथा विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया के बीच संबंध क्या है?

**12वीं पास की खबर का खंडन,लेकिन मूल सवाल जस के तस**-एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित खबर के बाद विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि 13 नमूना सहायकों को बिना योग्यता के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं बनाया गया है, विभाग ने पेज तीन पर सभी 13 कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण देते हुए बताया है कि संबंधित कर्मचारियों की योग्यता का परीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति ने किया था,विभाग के दस्तावेज में सूचीबद्ध योग्यताओं में एमएससी रसायन शास्त्र,एमएससी बायोटेक्नोलॉजी,एमएससी माइक्रोबायोलॉजी,एमएससी बायोकेमिस्ट्री और अन्य संबंधित योग्यताएं शामिल हैं,एक कर्मचारी की योग्यता बीटेक कृषि अभियांत्रिकी भी बताई गई है,यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है की अगर ये कर्मचारी इतनी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते थे,तो ये नमूना सहायक बने क्यों? क्या उनकी नियुक्ति के समय यही योग्यताएं उनके पास थीं? अगर थीं,तो उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधे भर्ती क्यों नहीं किया गया? अगर उस समय वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए पात्र नहीं थे,तो बाद में पात्रता कैसे और किस नियम के तहत बनी? और अगर उनकी डिग्री उस समय भी मान्य थी, तो क्या उन युवाओं और अभ्यर्थियों के अवसर पर कोई असर नहीं पड़ा जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया या प्रतियोगी परीक्षा का रास्ता चुना? इन सवालों का जवाब केवल वर्तमान शैक्षणिक योग्यता की सूची दिखाने से नहीं मिलता।

**FSSAI के नियम में उच्च शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान**-यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आता है,FSSAI के खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के नियम 2.1.3 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए विभिन्न संबंधित विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट स्तर की योग्यताओं का प्रावधान है,इनमें फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी,बायोटेक्नोलॉजी,ऑयल टेक्नोलॉजी,कृषि विज्ञान,पशु चिकित्सा विज्ञान,बायोकेमिस्ट्री,माइक्रो बायोलॉजी,केमिस्ट्री और मेडिसिन आदि शामिल हैं। साथ ही निर्धारित प्रशिक्षण की शर्त भी है,2025 में FSSAI ने कुछ चिकित्सा पाठ्यक्रमों को भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान्यता प्राप्त विषयों में जोड़ा था,इसलिए विवाद का केंद्र केवल यह नहीं होना चाहिए कि'डिग्री है या नहीं'असली जांच यह होनी चाहिए कि किस कर्मचारी की कौन-सी डिग्री,किस तारीख को प्राप्त हुई,उस समय लागू नियम क्या था और उस योग्यता के आधार पर उसकी पदोन्नति किस वैधानिक प्रक्रिया से हुई।

**25% कोटा...सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यहीं से जुड़ती है**-विभाग की प्रेस विज्ञप्ति स्वयं स्वीकार करती है कि भर्ती नियम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है,विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने 6 मई 2026 के राजपत्र के माध्यम से संबंधित भर्ती नियम में संशोधन करते हुए विभागीय पदोन्नति का प्रतिशत 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया,यही संशोधन पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है,क्यों? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि सरकार को भर्ती नियम बदलने का अधिकार है या नहीं,सरकार को नियम बदलने का अधिकार है,सवाल है की 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने की जरूरत कब महसूस हुई? इसका प्रस्ताव कब तैयार हुआ? फाइल किस तारीख को चली? किस अधिकारी ने प्रस्ताव रखा? क्या यह संशोधन पहले से लंबित था? यदि पहले से लंबित था तो कितने समय से? और सबसे महत्वपूर्ण है की क्या इस संशोधन का सीधा संबंध उन 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति से था? इन सवालों का जवाब फाइल नोटिंग, प्रस्ताव,अनुमोदन और राजपत्र की प्रक्रिया से ही स्पष्ट हो सकता है।

**तीन महीने पहले नियम बदला,फिर पदोन्नति संयोग या प्रशासनिक आवश्यकता?**-यदि 6 मई 2026 को पदोन्नति का कोटा 10 से 25 प्रतिशत किया गया और इसके बाद 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया,तो घटनाक्रम की टाइमलाइन सार्वजनिक होना चाहिए,पहले प्रस्ताव बना या पदोन्नति की जरूरत सामने आई? पहले पद रिक्तियों की गणना हुई या कोटा बढ़ाया गया? पहले डीपीसी की तैयारी हुई या नियम संशोधन हुआ? क्या 25 प्रतिशत कोटा सामान्य मानव संसाधन आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाया गया या तत्कालीन पदोन्नति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर? इन सवालों का उत्तर मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि नियम में संशोधन और उसके बाद हुई पदोन्नति को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय उनकी प्रशासनिक टाइमलाइन देखना आवश्यक है, विभाग यदि यह कहता है कि संशोधन पहले से प्रस्तावित था तो प्रस्ताव की पुरानी तारीख सामने रखी जा सकती है,यदि ऐसा नहीं है, तो सवाल और गंभीर हो जाता है।

**भर्ती और पदोन्नति दोनों रास्ते हैं,लेकिन प्राथमिकता किसे?**-विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है,तो फिर यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उस समय कुल कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत थे और कितने रिक्त थे,कितने पद सीधी भर्ती के लिए निर्धारित थे? कितने पद पदोन्नति के लिए? क्या सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी? क्या पदोन्नति पहले कर दी गई? अगर पदोन्नति पहले हुई तो उसका प्रशासनिक कारण क्या था? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पदोन्नति का रास्ता नियम में होना अलग बात है और उस रास्ते को किस समय इस्तेमाल किया गया,यह अलग प्रशासनिक प्रश्न है।

**'10 साल का अनुभव' भी बना जांच का विषय**-विभाग ने अपने खंडन में एक और महत्वपूर्ण बात कही है, उसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता के साथ नमूना सहायक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करना आवश्यक था,विभागीय पदोन्नति समिति ने संबंधित कर्मचारियों की पात्रता और दस्तावेजों का परीक्षण किया,अब यहां भी कई दस्तावेजी सवाल हैं 13 कर्मचारियों की मूल नियुक्ति की तारीख क्या है? उनकी नियुक्ति किस भर्ती नियम के तहत हुई? नियुक्ति के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी? 10 वर्ष की सेवा किस तारीख को पूरी हुई? क्या सभी 13 कर्मचारी एक ही तारीख अथवा अलग-अलग तारीखों में पात्र हुए? पदोन्नति के समय वरिष्ठता सूची क्या थी? क्या सभी पात्र कर्मचारियों पर समान मानदंड लागू किया गया? यदि इन सभी प्रश्नों के दस्तावेज उपलब्ध हैं तो विवाद समाप्त करने में विभाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

**डीपीसी ने जांच की तो डीपीसी की पूरी कार्यवाही सार्वजनिक क्यों नहीं?**-विभाग का सबसे मजबूत बचाव ही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है, विभाग कहता है कि विभागीय पदोन्नति समिति ने गहन जांच की, तो फिर जनता को यह जानने का अधिकार क्यों न हो कि समिति ने क्या जांच की? डीपीसी में कौन-कौन सदस्य थे? बैठक कब हुई? कुल कितने कर्मचारी पात्र थे? कितनों के दस्तावेजों की जांच हुई? किस कर्मचारी की कौन-सी डिग्री स्वीकार की गई? क्या किसी कर्मचारी की योग्यता पर आपत्ति आई? क्या किसी कर्मचारी का नाम पात्रता सूची से बाहर हुआ? वरिष्ठता सूची का आधार क्या था? डीपीसी की अनुशंसा किस अधिकारी ने मंजूर की? इन सवालों के जवाब डीपीसी की कार्यवाही और संबंधित नोटशीट से मिल सकते हैं।

**प्रतियोगी परीक्षा बनाम विभागीय पदोन्नति...अंतर समझना होगा**-खाद्य सुरक्षा अधिकारी तकनीकी और नियामकीय जिम्मेदारी वाला पद है,FSSAI के नियमों में शैक्षणिक योग्यता के साथ प्रशिक्षण की शर्त भी है,ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है,तो विभागीय पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के लिए कौन-सी चयन प्रक्रिया लागू होती है? क्या केवल वरिष्ठता और शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त है? क्या कोई विभागीय परीक्षा हुई? क्या दक्षता परीक्षण हुआ? क्या प्रशिक्षण कराया गया? या भर्ती नियम में विभागीय पदोन्नति के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित है? इसका जवाब भर्ती नियम की संबंधित अनुसूची और डीपीसी की कार्यवाही से ही तय होगा,इसलिए इस सवाल पर बिना दस्तावेज किसी कर्मचारी की योग्यता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा,लेकिन विभाग से पारदर्शी जवाब मांगना बिल्कुल उचित है।

**प्रेस विज्ञप्ति में हस्ताक्षर का सवाल भी क्यों महत्वपूर्ण?**-चार पेज की प्रेस विज्ञप्ति के अंतिम हिस्से में नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,छत्तीसगढ़ का पदनाम अंकित है,दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी हैं,अब यदि यह दावा किया जा रहा है कि हस्ताक्षर नियंत्रक के नहीं बल्कि किसी अन्य अधिकृत अधिकारी जैसे सहायक औषधि नियंत्रक एवं स्थापना शाखा प्रभारी द्वारा किए गए हैं,तो सवाल सीधा है,क्या संबंधित अधिकारी को नियंत्रक की ओर से इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का विधिवत अधिकार प्राप्त था? यह किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है,यह केवल प्राधिकरण की वैधता से जुड़ा प्रशासनिक सवाल है,यदि प्राधिकरण आदेश है तो उसे सार्वजनिक किया जा सकता है,इससे यह विवाद भी तत्काल समाप्त हो जाएगा।

**डीपीसी के सदस्यों को लेकर भी पारदर्शिता जरूरी**-इस पूरे मामले में डीपीसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभाग स्वयं अपने खंडन में समिति की जांच को पदोन्नति का आधार बता रहा है,ऐसे में समिति के गठन को लेकर उठने वाले सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,यदि किसी सदस्य के खिलाफ न्यायालय में कोई मामला लंबित है,कोई विभागीय विवाद है अथवा उसकी भूमिका को लेकर कोई आपत्ति है,तो केवल इस आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता,लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि क्या डीपीसी सदस्यों के चयन के लिए कोई स्पष्ट मानदंड था? क्या हितों के टकराव से बचने की कोई व्यवस्था अपनाई गई? क्या सभी सदस्यों ने निष्पक्षता संबंधी घोषणा की? और सबसे महत्वपूर्ण है की क्या डीपीसी की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड पर उपलब्ध है?

**विभाग ने आरोप का खंडन किया, लेकिन आरोपों की तह तक जाने की जरूरत अभी बाकी**-इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि विभाग ने प्रकाशित खबर को'पूर्णतःअसत्य,निराधार एवं काल्पनिक' बताया है,लेकिन एक मजबूत खंडन केवल यह बताने से पूरा नहीं होता कि 'हमने नियम के अनुसार किया।'अगर सवाल नियम पर है तो नियम की प्रति दीजिए,अगर सवाल योग्यता पर है तो नियुक्ति के समय की योग्यता बताइए,अगर सवाल 25 प्रतिशत कोटा पर है तो प्रस्ताव की फाइल दिखाइए,अगर सवाल पदोन्नति पर है तो डीपीसी की कार्यवाही बताइए,अगर सवाल वरिष्ठता पर है तो वरिष्ठता सूची सामने रखिए,अगर सवाल सीधी भर्ती पर है तो भर्ती प्रक्रिया की स्थिति बताइए,और अगर सवाल प्रेस विज्ञप्ति के हस्ताक्षर पर है तो अधिकृत अधिकारी का आदेश बताइए,दस्तावेज सामने आएंगे तो विवाद स्वतः खत्म हो जाएगा।

**सवाल किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं, व्यवस्था की पारदर्शिता के पक्ष में**-यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी कर्मचारी की डिग्री,योग्यता या पदोन्नति पर अंतिम फैसला समाचार रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया जा सकता,यदि विभाग के पास वैध नियम, पात्रता और डीपीसी की विधिवत अनुशंसा है तो वही निर्णायक दस्तावेज होंगे,लेकिन उसी तरह किसी खबर को केवल 'निराधार' कह देने से भी सभी सवाल समाप्त नहीं हो जाते,खाद्य सुरक्षा अधिकारी का काम सीधे जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है,इसलिए इस पद पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, विभाग की विश्वसनीयता उतनी ही मजबूत होगी।

**मामले को एक झटके में स्पष्ट करने के लिए विभाग यदि निम्न दस्तावेज सार्वजनिक कर दे तो विवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है:-**

1. 6 मई 2026 के भर्ती नियम संशोधन की अधिसूचना।
2. 10 से 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा बढ़ाने की फाइल/प्रस्ताव की तारीख।
3. कुल स्वीकृत एवं रिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों की स्थिति।
4. 13 पदोन्नत कर्मचारियों की मूल नियुक्ति आदेश की प्रतियां।
5. उनकी नियुक्ति के समय उपलब्ध शैक्षणिक योग्यता।
6. वर्तमान पदोन्नति की पात्रता सूची एवं वरिष्ठता सूची।
7. डीपीसी की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा।
8. सीधी भर्ती के 75 प्रतिशत कोटे की वर्तमान स्थिति।
9. पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रिया, यदि लागू हो।
10. प्रेस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का प्राधिकरण आदेश,यदि हस्ताक्षरकर्ता नियंत्रक स्वयं नहीं हैं।

**खंडन नहीं,दैनिक घटती-घटना के सवालों का जवाब दीजिए**-जिस प्रतिष्ठित अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग खंडन छपवाने की कवायद में जुटा,उसी मामले पर दैनिक घटती घटना करीब 50 खबरों के जरिए लगातार सवाल उठा चुका है, अब जरूरत खंडन की नहीं,उन सवालों के तथ्यात्मक और दस्तावेजी जवाब की है,एक प्रतिष्ठित अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने उसका खंडन जारी कर दिया, लेकिन दैनिक घटती-घटना इस पूरे मामले पर शुरुआत से लगातार खबरें प्रकाशित कर कई गंभीर सवाल उठा चुका है, अब तक इस मामले में करीब 50 खबरें प्रकाशित होने की स्थिति बन रही है, ऐसे में सवाल यह है कि यदि विभाग के पास पूरे मामले में नियमसम्मत प्रक्रिया और पारदर्शिता के पर्याप्त दस्तावेज हैं,तो उन सवालों का जवाब सीधे दैनिक घटती-घटना को क्यों नहीं दिया जा रहा? खंडन किसी एक खबर का जवाब हो सकता है,लेकिन लगातार उठाए जा रहे सवालों का विकल्प नहीं,दैनिक घटती-घटना ने जिन बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं,उनमें 13 नमूना सहायकों की मूल नियुक्ति,उनकी नियुक्ति के समय की शैक्षणिक योग्यता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की निर्धारित पात्रता,10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए गए पदोन्नति कोटे की टाइमिंग,राजपत्र संशोधन की प्रक्रिया, सीधी भर्ती और पदोन्नति के क्रम तथा विभागीय पदोन्नति समिति की भूमिका जैसे सवाल शामिल हैं,विभाग की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे और 13 कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है,इसलिए अब सवाल किस अखबार ने क्या लिखा? का नहीं,बल्कि दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार उठाए गए सवालों का जवाब क्या है? का है।

### प्रतिष्ठित अखबार को भी सवाल पूछना चाहिए

यदि विभाग किसी प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित खबर को गलत बताकर खंडन जारी कर सकता है, तो उसी गंभीरता से यह भी पूछा जाना चाहिए कि दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार प्रकाशित खबरों में उठाए गए सवालों का जवाब विभाग ने अब तक क्यों नहीं दिया? क्या विभाग के पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं? या जवाब हैं,लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है? यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप हुआ है,तो नियुक्ति आदेश,भर्ती नियम, राजपत्र संशोधन,डीपीसी की कार्यवाही,पात्रता सूची और पदोन्नति से संबंधित दस्तावेज सामने रखे जाने चाहिए,क्योंकि करीब 8 महीने में 50 खबरों के बाद भी यदि सवाल वहीं खड़े हैं,तो एक प्रेस विज्ञप्ति से मामला खत्म नहीं होगा,अब खंडन नहीं–दस्तावेज चाहिए,जवाब चाहिए और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता चाहिए।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)